



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]
No. 205]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2003/श्रावण 31, 1925
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2003/SRAVANA 31, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2003

अंतिम निष्कर्ष

विषय : चीन जनवादी गणराज्य तथा इंडोनेशिया मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लोट ग्लास के आयात के सम्बन्ध में पाटनरोधी जांच।

सं. 14/19/2002-डीजीएडी.— वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन एवं संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 को ध्यान में रखते हुए:

क. प्रक्रिया

2. जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई:-

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) को उपरोक्त नियमावली के अधीन घरेलू उद्योग की ओर से ऑल इंडिया फ्लोट ग्लास मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईएफजीएमए), नई दिल्ली की ओर से लिखित याचिका प्राप्त हुई जिसमें चीन जनवादी गणराज्य तथा इंडोनेशिया (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए फ्लोट ग्लास (जिसे इसके बाद संबद्ध माल भी कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है :

- (ii) भारत में फ्लोट ग्लास के निम्नलिखित उत्पादकों तथा ऑल इंडिया फ्लोट ग्लास मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदस्यों (जिन्हें इसके बाद याचिकाकर्ता कहा गया है) ने विशेष रूप से पाटनरोधी जांच में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की है:

- क) मै० सेंट गोबेन ग्लास इंडिया लि०, कांचीपुरम, तमिलनाडु
ख) मै० फ्लोट ग्लास इंडिया लि०, मुंबई

एक अन्य घरेलू उत्पादक, अर्थात् मै० गुजरात गार्डियन लि०, जिला भरूच, गुजरात ने याचिका का समर्थन किया है।

- (iii) प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य और इंडोनेशिया के भारत में स्थित दूतावासों को उपरोक्त नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जांच को शुरू करने की कार्रवाई से पहले याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए पाटन संबंधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे सूचित किया।
- (iv) प्राधिकारी ने 5 जुलाई, 2002 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसके द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची-I के अध्याय शीर्ष/उपशीर्ष 70.05 में शामिल फ्लोट ग्लास के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू की गई।
- (v) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और शिकायतकर्ताओं को भेजी और उन्हें अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराने का अवसर प्रदान किया।
- (vi) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6 के उप-नियम (3) के अनुसार याचिका की एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों तथा भारत में सम्बद्ध देशों के दूतावासों को भेजी।
- (vii) संबद्ध माल के आयात-ब्यौरे उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) से अनुरोध किया गया :

- (viii) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात देशों तथा दूतावासों को याचिका के अगोपनीय रूपांतर की प्रतियां उपलब्ध कराई :
- (ix) जांच आरंभ किए जाने के बारे में नियम 6(2) के अनुसार संबद्ध देशों के दूतावासों को सूचना दी गई और उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को यह सलाह दे दें कि वे प्रश्नावली का निर्धारित समयावधि के भीतर प्रत्युत्तर भेज दें । उन्हें पत्र, याचिका तथा निर्यातकों को भेजी गई प्रश्नावली की एक-एक प्रति भी भेजी गई :
- (x) संबद्ध माल के भारत के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं (प्रारंभिक जांच के ब्यौरों के यथानुसार) को एक प्रश्नावली भेजी गई और उनसे नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी मांगी गई :
- (xi) प्राधिकारी ने दिनांक 20 नवंबर, 2002 की अधिसूचना द्वारा प्रारंभिक निष्कर्षों को अधिसूचित किया और इच्छुक पक्षकारों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने विचार इसके प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित रूप में उपलब्ध करा दें:
- (xii) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के दूतावासों को भी प्रारंभिक निष्कर्षों की एक-एक प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे संबद्ध माल के निर्यातकों/उत्पादकों और अन्य पक्षकारों को यह सलाह दे दें कि वे प्रारंभिक निष्कर्षों पर अपने-अपने विचार उपर्युक्त निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर दें :
- (xiii) प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों की एक-एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों (जिनके ब्यौरे याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए थे), अन्य निर्यातकों जिन्होंने जांच-प्रारंभ अधिसूचना का प्रत्युत्तर दिया, भारत के आयातकों को प्रेषित की और उनसे अनुरोध किया गया कि वे प्रारंभिक निष्कर्षों पर अपने-अपने विचार, यदि कोई हों, पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दें:
- (xiv) प्राधिकारी ने इच्छुक पक्षकारों को इस बात का अवसर प्रदान किया कि वे दिनांक 19 फरवरी, 2003 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप

में प्रस्तुत करें। अपने-अपने विचार प्रस्तुत कर रहे सभी पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे अपने अपने प्रस्तुत विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। इन पक्षकारों को सलाह दी गई थी कि वे विरोधी पक्षकारों द्वारा व्यक्त विचारों की प्रतियां एकत्र करें और उनका खंडन, यदि कोई हो, करें:

(xv) प्राधिकारी ने विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय भाग संबंधी सार्वजनिक फाइल नियम 6(7) के अनुसार सभी इच्छुक पक्षकारों को उनके अनुरोध पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराई:

(xvi) इच्छुक पक्षकारों द्वारा किए गए तर्क-वितर्कों की जिनकी घोषणा प्रारंभिक निष्कर्षों से पहले की गई और जिन्हें अधिसूचित प्रारंभिक निष्कर्षों में प्रकाशित किया है, संक्षिप्तता के प्रयोजनार्थ पुनरावृत्ति नहीं की गई है। तथापि, इच्छुक पक्षकारों द्वारा बाद में किए गए तर्क प्रकटीकरण विवरण-पत्र तथा इन निष्कर्षों में समुचित रूप से शामिल किए गए हैं:

(xvii) उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए आवश्यक तथ्यों/आधार को एक प्रकटीकरण विवरण-पत्र द्वारा दिनांक 25 जून, 2003 को ज्ञात इच्छुक पक्षकारों को बता दिया गया और उस पर प्राप्त टिप्पणियों को इन निष्कर्षों में शामिल किया गया है:

(xviii) घरेलू उद्योग की मौके पर पड़ताल (जैसा कि आवश्यक समझा गया) सहित लागत जांच भी की गई ताकि अनुकूल उत्पादन-लागत तथा सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर संबद्ध माल के विनिर्माण तथा बिक्री की लागत का आकलन किया जा सके :

(xix) प्राधिकारी ने निर्यातक-मैसर्स पी टी म्यूलिया, इंडोनेशिया द्वारा प्रस्तुत जानकारी की मौके पर पड़ताल की:

(xx) इस अधिसूचना में *** पर वह जानकारी है जो गोपनीय आधार पर इच्छुक पक्षकारों द्वारा दी गई है और प्राधिकारी ने नियमावली के तहत ऐसा समझा है:

(xxi) जांच में दिनांक 1 अप्रैल, 2001 से 31 दिसंबर, 2001 तक की अवधि शामिल की गई है:

(xxii) प्रारंभ सूचना तथा प्रारंभिक निष्कर्षों की प्रतियां फिक्की, सी आई आई, ऐसोचैम, आदि को भी व्यापक परिचालन हेतु भेजी गई।

ख. याचिकाकर्ताओं, निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य इच्छुक पक्षकारों के विचार और प्राधिकारी द्वारा जांच:

3. विभिन्न इच्छुक पक्षकारों द्वारा व्यक्त विचारों की चर्चा प्रारंभिक निष्कर्षों तथा प्रकटन विवरण-पत्र में की गई है, जिन विचारों की चर्चा पहले प्रारंभिक निष्कर्षों और प्रकटन विवरण-पत्र में नहीं की गई है और जिन्हें प्रकटन विवरण-पत्र के प्रत्युत्तर में उठाया गया है उन्हें नियमानुसार यथावांछित सीमा तक तथा इस मामले के संबंध के अनुसार अगले संगत पैराग्राफों में प्रस्तुत किया गया है। इच्छुक पक्षकारों द्वारा दी गई गई दलीलों की जांच की गई, उन पर विचार किया गया और यथावश्यकतानुसार उन पर अगले पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4. प्रारंभिक निष्कर्षों के स्तर पर निम्नलिखित से उत्तर प्राप्त हुए थे:-

निर्यातक

- (i) पी टी मुलिया ग्लास, इंडोनेशिया
- (ii) पी टी बाब्दी रक्यात बक्ति, इंडोनेशिया
- (iii) पी टी टेंसिडो, इंडोनेशिया
- (iv) मैसर्स विचनहुयांगडाओ हौइनो ग्लास कं० लि०, चीन
- (v) मैसर्स नार्निंग फ्लोट ग्लास कं० लि०, चीन

आयातक

- (i) मै० मोनिका एग्जिम इंटरनेशनल लि०, पुणे
- (ii) मै० लिबर्टी ग्लास हाऊस, मुंबई
- (iii) मै० इम्पैक्ट सेफ्टी ग्लास वर्क्स प्रा० लि०, बंगलौर
- (iv) मै० महावीर मिरर इण्डस्ट्रीज

- (v) मै0 टी.एल. वर्मा एंड कंपनी (प्रा0) लि0
- (vi) मै0 समर्थ इंडस्ट्रीज, मुंबई
- (vii) मै0 राजवी इन्टरप्राइज, मुंबई
- (viii) मै0 चिनोय चाबलानी एंड कंपनी, कलकत्ता

विभिन्न इच्छुक पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों का जिक्र प्रारंभिक निष्कर्षों में कर दिया गया है अतः सक्षिप्तता के प्रयोजनार्थ उनकी पुनरावृत्ति यहां नहीं की जा रही है।

मै0 मोनिका ऐक्विम इन्टरनैशनल लि0, पुणे तथा मैसर्स नवाकर इंपेक्स प्रा0 लि0, चेन्नई द्वारा प्रकटन के प्रत्युत्तर में व्यक्त विचार

5. ऐसी दलील दी गई है कि प्राधिकारी द्वारा जारी प्रकटनों में निम्नलिखित कमियां हैं:-

प्रारंभ: आवेदन याचिकाकर्ताओं तथा समर्थकों के किसी पत्र के बिना था ।

प्रक्रिया: अनेक इच्छुक पक्षकारों को दिनांक 5.7.2002 के प्रारंभ-अधिसूचना की प्रति नहीं भेजी गई और उनके नाम सूची में प्रकट नहीं किए गए । यहां तक कि विदेशी निर्यातकों जैसे पी टी टेंसिण्डों तथा पी टी आब्दी राक्यात बक्ती को प्रारंभिक निष्कर्षों की प्रति नहीं भेजी गई और उन्हें दिनांक 19.2.2003 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई की सूचना नहीं दी गई ।

सिविल अपील का अप्रकटीकरण: न्यायालयों में लंबित मामलों/माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेशों के तथ्य का प्रकटीकरण में उल्लेख नहीं किया गया है।

जांच की अवधि: जांच आरंभ करने से पहले यह आवश्यक था कि परावर्ती ग्लास आयातकों फ्लोट ग्लास से अलग कर दिया जाता । आरंभ जुलाई, 2002 में अर्थात् पी ओ आई की अन्तिम तारीख से सात माह बाद किया गया ।

विचारार्थ उत्पाद तथा समान वस्तु: यह प्रकट नहीं किया गया कि मद-शीट ग्लास की उत्पादन मात्रा को समान वस्तु के रूप में क्यों नहीं समझा जाता है । यदि शीट

ग्लास के उत्पादन को ऐसा समझा जाता है तो याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की परिभाषा में नहीं आते हैं ।

पाटन मार्जिन

- (क) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह प्रकट नहीं किया है कि चीन के विनिर्माताओं के मामले में पी टी मूलिया के सामान्य मूल्य की बजाए घरेलू याचिकाकर्ताओं की बनावटी विनिर्माण लागत को सामान्य मूल्य मानेका क्या कारणा है । प्राधिकारी को चाहिए कि वह घरेलू याचिकाकर्ताओं की अत्यधिक ऊंची विनिर्माण लागत की बजाए पी टी मूलिया के सामान्य मूल्य पर विचार करें ।
- (ख) प्राधिकारी ने चीन के विनिर्माता से उत्तर प्राप्त हुए बिना ही यह प्रकट कर दिया कि पाटन मार्जिन प्राप्त करने हेतु चीन से निर्यात कीमत-प्रमाण की गणना कैसे की गई है ।
- (ग) प्राधिकारी सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा भारित औसत आधार पर पाटन मार्जिन की गणना के कारण बताने में असफल रहा है ।
- (घ) पी टी मूलिया द्वारा उपलब्ध कराया गया सामान्य मूल्य अन्य इण्डोनेशियाई सप्लायरों हेतु समर्थित मूल्य है । तीन विनिर्माताओं के लिए निर्यात कीमत एक समान है, विशेष रूप से 4 एम एम तथा 5 एमएम क्लीयर फ्लोट ग्लास के मामले में । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने त्रुटियुक्त गणना को प्रकट नहीं किया है। चूंकि सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत तीनों विनिर्माताओं के लिए एक समान है अतः पी टी टेंसिण्डों तथा पी टी आब्दी के पाटन मार्जिन की तुलना पी टी मूलिया से मार्जिन से तुलना करने में अधिक कैसे हो सकती है ।

क्षति का मूल्यांकन

- संबद्ध देशों से आयात: वार्षिक आयात आंकड़ों का जिन्हें प्रकट नहीं किया गया है, संबद्ध देशों से आयात-मात्रा में वृद्धि दिखाने में प्रयोग किया गया जबकि वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं किए गए हैं । कुल आयात-मात्रा में वर्ष 1999-2000 की तुलना में अत्यधिक गिरावट रही है । वर्ष 1999-2000 के दौरान

बताया गया है कि आयात 10272 मी० टन हुआ जबकि जांच-अवधि में यह घटकर 4406 एम टी और वार्षिकीकृत 5874.67 एम टी रहा ।

आवेदन की सारणी 4.1 से यह भी विदित होगा कि संबद्धदेशों से आयात देश में मांग की तुलना में जो 1999-2000 में 9.15% की कमी रही थी अत्यधिक घटकर 2000-01 में 1.71 रह गए और यह जांच अवधि के दौरान 3.32% रह गए, यद्यपि देश की कुल मांग अत्यधिक बढ़कर 100 से 118.18 हो गई ।

- बाजार हिस्सा: ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं ने जांच अवधि के लिए संबद्ध माल की बिक्री मात्रा के मात्र वार्षिकीकृत आंकड़े दिए हैं जबकि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय वास्तविक आंकड़े उपलब्ध थे । निर्दिष्ट प्राधिकारी के विश्वसनीय वार्षिकीकृत बिक्री मात्रा के आंकड़े नहीं बताए गए हैं ।

यह बात नहीं बताई गई है कि देश में संबद्ध माल की मांग के संबंध में उसकी मांग में वृद्धि कैसे हो गई । वास्तव में, इस बात को प्रकट किया गया है कि उक्त मांग में घरेलू उद्योग की तुलना में गिरावट आई है ।

संबद्ध माल के बाजार मांग-आंकड़ों का जो अगोपनीय किस्म के होते हैं, खुलासा नहीं किया गया है, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मूल्यांकन क्षति-मापदण्डों में इन आंकड़ों का प्रयोग किया है ।

- घरेलू उद्योग का उत्पादन: संबद्ध माल के लिए याचिकाकर्ताओं की प्रतिस्थापित क्षमता नहीं बताई गई है । प्रतिस्थापित क्षमता का महत्व पूंजी निवेश तथा प्रचालन-स्तर और घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई तथा अपनाई गई पूंजी-आय की जांचकरने में होता है ।

घरेलू उद्योग के संबंधमें पूंजी उपयोग के अनुकूल तथा वास्तविक तथा वास्तविक आंकड़ों का खुलासा नहीं किया गया है ।

निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह बात नोट की है कि उत्पादन-क्षमता में वृद्धि हुई है और इस वृद्धि से क्षमता-उपयोग में 0.66% की मामूली गिरावट आई है । निर्दिष्ट प्राधिकारी यह बात दर्शाने में असफल रहा है कि इस पर क्षति का दावा कैसे

किया जा सकता है। वास्तव में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस बारे में बेहतर निष्पादन को प्रकट नहीं किया है।

निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि समर्थक कंपनी मैसर्स गुजरात गर्डियन जांच-अवधि के दौरान लगभग 110% क्षमता पर चल रही थी।

घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में लगातार वृद्धि होती रही है और जब घरेलू उद्योग इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, तब ऐसा कोई कारण नहीं बनता है कि आयातों की वजह से क्षति होगी और इसीलिए, आयातों के कारण कोई क्षति हुई हो अथवा इसे सिद्ध किया गया हो। 80% के लगभग क्षमता-उपयोग पूरे विश्व में सामान्यतया अनुकूल समझा जाता है और क्षमता-उपयोग में 0.66 प्रतिशत की मामूली गिरावट नई क्षमता में वृद्धि की वजह से भी हो सकती है।

- बिक्री मात्रा: उचित बिक्री कीमत की गणना के तथाकथित मानदण्डीय आधार का खुलासा नहीं किया गया है। यह नहीं बताया गया है कि कुछ व्याख्याहीन 'अन्य कारकों' की वजह से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को कैसे रद्द किया गया, ये 'कुछ कारक' क्या-क्या हैं, इसका खुलासा नहीं किया गया है।

यह नोट करना प्रासंगिक है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात को स्वीकार करने में संतुष्टि कैसे हुई कि घरेलू उद्योग के इस दावे को स्वीकार किया जाए कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में हुई वृद्धि को देश में नई क्षमता-वृद्धि के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यदि ऐसा है कि बाजार हिस्से में नई क्षमता लगाने से वृद्धि होती है तो आयात होने का डर क्यों बना रहे क्योंकि आयात-वृद्धि का होना नई क्षमता में वृद्धि होना है क्योंकि बाजार बढ़ी हुई क्षमता की खपत करने में सक्षम है।

- माल सूची: निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह खुलासा नहीं किया है कि माल सूची की तुलना मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष की तुलना में दिसंबर, 2001 को समाप्त वर्ष की माल सूची से तुलना करने का क्या कारण है। माल सूची की तुलना वर्षान्त से वर्षान्त अथवा दिसम्बर, 2001 की तुलना दिसंबर, 2000 से की जा सकती है ताकि सही तुलना की जा सके।

- रोजगार: निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इस आधार पर कोई क्षति नहीं हुई है ।
- मजदूरियां: निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह खुलासा नहीं किया है कि क्षति इस कारया नहीं हुई है ।
- लाभप्रदता: निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह प्रकट नहीं किया है कि घरेलू उद्योग ने जांच-अवधि के दौरान उसके पिछले सम्पूर्ण इतिहास की तुलना में अधिकतम लाभ कमाया । इसके अतिरिक्त, यह भी नहीं बताया गया है कि याचिकाकर्ता कम्पनी मैसर्स सेन्ट गोबेन एक नई कंपनी है और इसने उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में निहित अनुमानों की तुलना में बेहतर परिणाम दिखाए हैं । यह भी नहीं दर्शाया गया है कि समर्थक कम्पनी गुजरात गार्डियन लि० ने जांच-अवधि के दौरान लगभग 50 करोड़ रू० का लाभ कमाया है ।
- बिक्री कीमत: संबद्ध माल के उत्पादन हेतु उत्पादन की अनुकूल तथा वास्तविक लागत का खुलासा नहीं किया गया है । यह नहीं बताया गया है कि बिक्री कीमत अथवा अहानिकर कीमत की जो घरेलू उद्योग को हुई बताई गई है, गणना किस प्रकार की गई है और इसमें तथा अनुमान लगाने में शामिल लागतें क्या-क्या हैं । उचित बिक्री कीमत अथवा अहानिकर कीमत जिसकी गणना-पद्धति, शामिल लागत, आधार तथा अनुमान का खुलासा नहीं किया गया है और आयात को बंदरगाह पर उतारते समय उसका मूल्य वास्तव में अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क है और इसलिए उचित कीमत अथवा अहानिकर कीमत के सम्पूर्ण आधार तथा गणना का खुलासा कर दिया जाना चाहिए था ।
- कीमत का कम निर्धारण: निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि घरेलू उद्योग ने जांच-अवधि में विगत ए.वाई. की तुलना में अपने उत्पाद की बिक्री कीमत में कम से कम 65% की वृद्धि की है । इसके चलते इस बात का दावा कैसे किया जा सकता है कि कीमत कम-निर्धारण अथवा हानि हुई है। यदि कीमत का कम निर्धारण हुआ है तो तब ऐसे में बिक्री कीमत में वृद्धि संभव नहीं थी । एडीए ने यह खुलासा नहीं किया है कि 'अन्य कारक' कौन-कौन से हैं जिनके कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में सुधार और कच्चे माल की कीमत में वृद्धि द्वारा हुई बिक्री कीमत में वृद्धि हुई बताई गई है ।

- पूंजी निवेश से आय: निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह प्रकट नहीं किया है कि विगत वर्ष में अधिक क्षमता के चलते किसी भी विनिर्माता के लिए उचित आर ओ आई संभव नहीं थी और इसके बावजूद जांच-अवधि के दौरान सबने बेहतर आरओआई दर्शाई है। प्राधिकारी ने यह नहीं बताया है कि याचिकाकर्ताओं से कितनी उचित आरओआई की उम्मीद है। समर्थक कम्पनी ने जांच-अवधि के दौरान अपनी पूंजी निवेश के 10% कर तथा ह्रास के बाद लाभ कमाया है। पूंजीनिवेश पर उचित तथा अवास्तविक आय किस का घरेलू उग पात्र बताया गया है, का एडीए ने प्रकटन विवरण-पत्र में खुलासा नहीं किया है। पूंजीनिवेश की उचित सीमा जिस पर उचित आय की गणना तथा अनुमान लगाए गए हैं, इसका खुलासा नहीं किया गया है।

वित्तीय सूचना यदि घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई है, के विश्लेषण और लगाई गई पूंजी पर घरेलू उद्योग की आय पर आयात-प्रभाव की जांच हेतु प्राधिकारी द्वारा की गई पड़ताल के परिणामों को प्रकट नहीं किया गया है।

इस विश्लेषण में अपनाई गई पद्धति नहीं दर्शायी गई अथवा उसकी व्याख्या नहीं की गई है। कीमत कम निर्धारण संबंधी सारणी में कोई ऐसे आंकड़े नहीं दिए गए हैं जिसका खुलासा सही कीमत कमी, यदि कोई हो, तय करने हेतु किया जा सकता है। कीमत-कमी आयातों के कारण नहीं बल्कि घरेलू विनिर्माताओं में प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है जिसमें फ्लोट ग्लास उद्योग की शीट ग्लास उद्योग को धीरे-धीरे समाप्त करने की योजना है।

- रोकड़ प्रवाह पर वास्तविक तथा संभाव्य नकारात्मक प्रभाव: निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस पहलू पर कोई विश्लेषण प्रकट नहीं किया कि याचिकाकर्ताओं का नकारात्मक रोकड़ प्रवाह अनेक अन्यकारकों के कारण रहा और उन कारकों को भी प्रकट नहीं किया गया है।
- वृद्धि: निर्दिष्ट प्राधिकारी ने समर्थक कम्पनी द्वारा किए गए अतिरिक्त पूंजी निवेश का खुलासा नहीं किया है।
- कारणात्मक संबंध:

निर्दिष्ट प्राधिकारी के ध्यान में यह बात बार-बार लाई गई है कि वह न केवल तथाकथित पाटन का अध्ययन करें बल्कि घरेलू उद्योग को पाटन के प्रभाव

तथा उससे हुई हानि का भी अध्ययन करें। निर्दिष्ट प्राधिकारी यह भी पड़ताल कर लें कि घरेलू उद्योग को क्षति केवल पाटन के प्रभाव से हो रही है इन दोनों के बीच स्पष्ट कारण संबंध हैं। और, यदि क्षति किसी और कारण से हो रही है तो वह है पाटन।

मौजूदा मामले में घरेलू उद्योग को क्षति तथाकथित पाटन के कारण नहीं हुई है। यह याचिकाकर्ताओं तथा समर्थकों के तुलन-पत्रों से बिल्कुल स्पष्ट है। यदि कोई क्षति पाई जाती तो तुलन-पत्रों में सकारात्मक की बजाए नकारात्मक निष्पादन दर्शाया जाता जब पिछले तीन वर्षों से तुलना की जाती, जैसाकि मौजूदा जांच के मामले में किया गया। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इसे प्रकट नहीं किया है।

नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है, यदि घरेलू तथा स्थानीय उत्पादकों में कोई प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धति मौजूद हो, कि इस कारण हुई क्षति का कारया पाटन नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का बार-बार उल्लेख किया है जिसमें यह दिखाया गया है कि इस मामले को कवर करने में एमआरटीपीसी तथा एडीडी के अलग-अलग क्षेत्राधिकार हैं। एमआरटीपीसी में तो घरेलू उत्पादकों को प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धति की वजह से हुई क्षति का मामला अभी भी लंबित है। यदि एमआरटीपी में याचिकाकर्ता को मिलने वाला कम कीमत के माल की सप्लाई से हुई क्षति में प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धति का दावा है तब जैसाकि एडीडी नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है, इस कारण हुई क्षति का आरोप पाटन पर नहीं लगाया जा सकता है। अन्य शब्दों में, एडीडी को चाहिए कि प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धति के कारण हुई क्षति की मात्रा को अलग कर दें और उसे पाटन, यदि कोई हो, के कारण हुई क्षति नहीं माना जाए।

- आयातों की कीमत, मूल्य तथा मात्रा और घरेलू उद्योग के बीच सही कारण-संबंध स्थापित अथवा प्रकट नहीं किए गए।

6. प्राधिकारी के विचार:

क) प्राधिकारी का विचार यह है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के तहत दिनांक 25 जून, 2003 को जारी प्रकटन विवरण-पत्र में प्राधिकारी के विचाराधीन व आवश्यक तथ्य शामिल हैं जो उसके अन्तिम निष्कर्षों का आधार बनेंगे। प्रारंभिक

निष्कर्षों के स्तर पर विभिन्न इच्छुक पक्षकारों के निवेदन बता दिए गए थे और उन्हें दिनांक 20.11.2002 की प्रारंभिक निष्कर्ष अधिसूचना के जारी होते समय देख लिया गया। नियम 16 के अनुसार प्रकटन विवरण-पत्र में प्राधिकारी के विचाराधीन आवश्यक तथ्य शामिल करने आवश्यक हैं जो कि अन्तिम निष्कर्ष देने में आधार की भूमिका बनेंगे। इस स्तर पर किसी पक्षकार द्वारा कोई नया मुद्दा शामिल किया जाए, इसकी अनुमति नहीं क्योंकि जांच आरंभ करने के बाद, प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद और सार्वजनिक सुनवाई के बाद इच्छुक पक्षकारों को अपनी-अपनी टिप्पणी देने हेतु पर्याप्त समय पहले ही दिया गया है।

ख) प्रारंभ के बारे में यह दलील कि प्रारंभन - आवेदन-पत्र के साथ याचिकाकर्ताओं तथा समर्थकों के पत्र नहीं लगे थे, याचिका में आल इण्डिया फ्लोट ग्लास मैन्यू0 एसोसिएशन का पत्र शामिल था। आयातक मैसर्स मोनिका ऐक्विजम इंटरनेशनल लि0 के अनुरोध पर उक्त पत्र की एक प्रति निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपने दिनांक 1 अक्टू., 2002 के पत्र द्वारा भेजी गई थी।

ग) प्रारंभन अधिसूचना तथा प्रारंभिक निष्कर्षों को विभिन्न इच्छुक पक्षकारों को भेजने संबंधी प्रक्रिया पर उठाए गए मुद्दों का जहां तक संबंध है, प्रारंभन अधिसूचना दिनांक 5.7.2002 को और प्रारंभिक निष्कर्ष दिनांक 20.11.2002 को सभी इच्छुक पक्षकारों, संबद्ध देशों के भारत स्थित दूतावासों और जांच में सहभागिता करने वाले निर्यातकों/आयातकों को भेजे गए। इस संबंध में प्रारंभिक निष्कर्ष अधिसूचना का पैरा-2 संबंधित है। प्राधिकारी को निर्यातक मैसर्स पी टी टेंसिण्डो से दिनांक 20.11.02 की प्रारंभिक निष्कर्ष अधिसूचना की पावती भी मिली है। जहां तक दिनांक 19.2.2003 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई का संबंध है, इसे दिनांक 22 जनवरी, 2003 को जारी किया गया और सभी इच्छुक पक्षकारों को सूचित किया गया। निर्यातक मैसर्स पी टी मुलिया ने अपने दिनांक 17.2.03 के ई-मेल द्वारा पुष्टि की कि उन्हें सार्वजनिक सुनवाई की सूचना मिल गई है और सूचित किया कि वे सार्वजनिक सुनवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। मैसर्स महावीर मिरर इण्डस्ट्रीज, चेन्नई, मैसर्स नवाकर इम्पैक्स प्रा0 लि0, चेन्नई ने सार्वजनिक सुनवाई की सूचना की पावती भेजी लेकिन वे इसमें शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने प्रारंभिक निष्कर्षों को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और न्यायालय के अन्तरिम आदेशों को देखते हुए अन्तिम निष्कर्षों सहित सभी अगले निर्णयों को लंबित रखना पड़ा। मैसर्स मोनिका ऐक्विजम इन्ट. लि0 ने न तो सार्वजनिक सुनवाई की सूचना का उत्तर दिया और ना ही वे सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित हुए। उद्योग मंत्रालय, इण्डोनेशिया गणराज्य

और इण्डोनेशिया के भारत स्थित दूतावास के प्रतिनिधि तथा अन्य सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित हुए। प्राधिकारी का विचार है कि पाटनरोधी नियम 6 के तहत विहित प्रक्रिया का विधिवत अनुपालन किया गया और इच्छुक पक्षकारों को यह अवसर दिया गया कि वे दिनांक 19.2.2003 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक निवेदन करें। सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित पक्षकारों ने तत्पश्चात् लिखित निवेदन किए जिन्हें परस्पर आदान-प्रदान किया गया। तत्पश्चात् इन पक्षकारों ने अन्य पक्षकारों के निवेदनों पर पुनरुत्तर दिए। कुछ आयातकों तथा निर्यातकों ने अपने ज्ञात कारणों से सार्वजनिक सुनवाई में भाग नहीं लिया, किंतु वे इस बात का दावा नहीं कर सकते कि उन्हें मौखिक सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया बल्कि उन्होंने प्रदान किए गए अवसर का लाभ नहीं उठाया है। माननीय उच्च न्यायालय से निर्दिष्ट प्राधिकारी को जांचमें आगे कार्रवाई करने से रोका नहीं गया। अतः प्राधिकारी को आयातकों की इस दलील में दम नहीं दिखाई देता है कि उसने जांच कार्रवाई में प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया है।

घ) जहां तक अन्य मुद्दों अर्थात् जांच अवधि, विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु, पाटन मार्जिन, क्षति मूल्यांकन के संबंध में दी गई दलील का संबंध है, उन पर चर्चा इन निष्कर्षों में समुचित स्थान पर की गई है।

7. माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं/अपीलें:

क) प्लोट ग्लास के कुछ आयातकों ने माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास में रिट याचिकाएं/अपील दायर की जिनमें दिनांक 20.11.2002 की प्रारंभिक निष्कर्ष अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी गई। मैसर्स महावीर मिरर इण्डस्ट्रीज की 2003 की रि० या० 1451 की रि० या० विविध या० 1812/2003, मैसर्स मोनिका ऐक्जिम इन्ट. लि० की 2003 रि० या० 3193 में रि० या० विविध या० 3985/2003 और मैसर्स नवाकर इम्पेक्स प्रा० लि० की 2003 की रि० या० 1449 में रि० या० 1810/2003। इन पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.1.03 और 3.2.03 को यह कहत हुए अन्तरिम आदेश जारी किए कि इस आशय का अन्तरिम स्थगनादेश किया जाएगा कि केन्द्रीय सरकार केवल नियम-13 के स्तर तक ही आगे कार्रवाई करेगी और अगला निर्णय अगले आदेश तक रोक लिया जाएगा। बाद में मैसर्स महावीर मिरर इण्ड. की रि० या० 44506 और 44507- वर्ष 2002 और मैसर्स मोनिका ऐक्जिम की 2003 की रिट याचिका 3193 तथा 3194 को माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास के दिनांक 13.3.2003 के आदेश द्वारा रद्द कर दी गई।

उक्त आयातकों ने अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 20.11.2002 के प्रारंभिक निष्कर्षों की वैधता और गोपनीयता जानकारी और प्रारंभिक निष्कर्षों को जारी करने से पहले व्यक्तिगत सुनवाई के रूप में वास्तविक न्याय के सिद्धांतों अननुपालन के संबंध में नियम 7 की वैधता को चुनौती दी थी। माननीय उच्च न्यायालय को इन आयातकों की रिट याचिकाओं में कोई औचित्य दिखाई नहीं दिया इसलिए उन्हें रद्द कर दिया गया।

ख) बाद में मै0 महावीर मिरर इंड. की रिट याचिका विविध 2091 और 2092/2003 तथा मै0 मोनिका एक्जिम इन्टर नै0 लि0 की रि0 या0 विविध या0 2093 तथा 2094/2003 के मामलों में माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास ने दि0 16 अप्रैल, 2003 को निम्नलिखित आदेश दिया:-

‘ इन सभी मामलों में दोनों वकीलों को सुनने के बाद और इस मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों और सुविधार्थ को देखते हुए हम निर्देश देते हैं कि इन सभी मामलों में माल की रिलीज पाटनरोधी शुल्क की बैंक गारंटी प्रस्तुत कर देने पर कीजाए। हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि रिट याचिकाएं स्वीकार करने पर बैंक गारंटी रद्द कर दी जाएगी अथवा अन्यथा पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करने में असफल होने की स्थिति में बैंक गारंटी की याचिका करनी होगी।’

माननीय न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों से यह स्पष्ट है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को जांचकी अगली कार्रवाई रोकने के कोई निर्देश नहीं हैं।

ग) जहां तक अन्य मुद्दों अर्थात् जांच-अवधि, विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु, पाटन मार्जिन, क्षति-मूल्यांकन पर दी गई दलीलों का संबंध है उन पर इन निष्कर्षों में समुचित स्थानों पर चर्चा की गई है।

8. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु:

वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद में स्वच्छ और रंगीन किस्म के 2 मिली मीटर से 12 मि. मी. (दोनों मोटाई शामिल हैं) मोटाई के फ्लोट ग्लास (हरे ग्लास को छोड़कर) शामिल हैं परंतु सजावट, औद्योगिक अथवा आटोमोटिव प्रयोजनों के लिए संसाधित ग्लास शामिल नहीं हैं।

प्रारंभिक निष्कर्षों के बाद निम्नलिखित विचार/टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं:

आल इण्डिया फ्लोट ग्लास मेन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (ए आई एफ जी एम ए) के विचार :

(i) विचाराधीन उत्पाद का विवरण विशिष्ट है और इसमें केवल स्पष्ट तथा रंगीन ग्लास कवर किया गया है। तदनुसार, उपर्युक्त उत्पाद परिभाषा में परावर्ती ग्लास शामिल नहीं किया जा सकता है जिसे प्रोसेस किया जाता है और वे स्पष्ट तथा रंगीन नहीं रह सकते जिससे वे पाटनरोधी जांच के दायरेमें आ सकें। एसोसिएशन का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि चीन तथा इण्डोनेशिया से आयाजित परावर्ती ग्लास पर पाटनरोधी शुल्क लगवाया जाए क्योंकि उनसे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई और यह एक संसाधित ग्लास है जिसका आयात फ्लोट ग्लास की अपेक्षा कहीं अधिक उंची कीमत पर किया जाता है। अतः अनुरोध है कि फ्लोट ग्लास पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने संबंधी अधिसूचना से परावर्ती ग्लास को हटा दिया जाए।

(ii) यह पूर्णतया स्पष्ट है कि 2 एम एम से कम और 12 एम एम से अधिक मोटे आकार को जांच के क्षेत्राधिकार के भीतर लाने का प्रस्ताव नहीं है और परावर्ती ग्लास भी जांच का हिस्सा नहीं है। आयातक द्वारा प्रस्तुत चार्ट में उन्होंने बताया है कि घरेलू उद्योग 3.2 एमएम, 5.5 एम एम आदि जैसे गैर-मानक मोटाई का उत्पादन नहीं करता है। इससंबंध में यह सादर प्रस्तुत है कि सामान्यतया ग्लास की बिक्री-मानक मोटाई में ही की जाती है और गैर-मानक मोटाई के ग्लास तकनीकी तथा वाणिज्य दोनों दृष्टियों से घरेलू उद्योग के उत्पाद श्रृंखला का पूर्णतया स्थानापन्न है। इस प्रकार, आयातक ऐसे किसी उत्पाद का उल्लेख नहीं कर सका है जो विचाराधीन उत्पाद अथवा घरेलू उद्योग की उत्पाद-श्रृंखला के समान हो। यह इस तथ्य के पूर्वाग्रह के बिना है कि आयातक का कथन कतिपय मोटाई के गैर-उत्पादन के संबंध में है, भी सही नहीं है।

इम्पैक्ट सेफ्टी ग्लास वर्क्स प्रा० लि०, बंगलौर के विचार:

भारत में फ्लैट ग्लास के और भी विनिर्माता हैं जो उक्त एसोसिएशन के हिस्से हैं और जो सदृश तथा स्थानापन्न मदों का उत्पादन करते हैं। याचिकाकर्ता ने ऐसी कंपनियों को भारतीय उत्पादक नहीं माना है। यदि इन कम्पनियों द्वारा उत्पादित उत्पाद समान उत्पाद नहीं है तो संगत मुद्दा ऐसा होगा कि क्या इण्डोनेशिया तथा चीन से आयातित उत्पाद समान उत्पाद हैं। भारतीय उत्पादक भी समान वस्तु का

उत्पादन कर रहे हैं। संबद्ध देशों से आयातित माल के संबंध में इन सभी उत्पादकों द्वारा संबद्ध देशों से उन्हें भारतीय उत्पादक नहीं माना गया है, द्वारा उत्पादित माल समान उत्पाद है। अतः याचिकाकर्ता द्वारा इन उत्पादकों को छोड़ा नहीं गया क्योंकि ये कम्पनियां ऐसो0 के सदस्य हैं।

मैसर्स मोनिका ऐक्विजम इन्टरनेशनल लि0 तथा मैसर्स नवाकर इम्पेक्स प्रा0 लि0 ने प्रकटन विवरण-पत्र के प्रत्युत्तर में यह मुद्दा उठाया है कि यह बात प्रकट नहीं की गई कि शीट ग्लास को समान वस्तु क्यों नहीं समझा गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच:

प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों का स्मरण करता है जिसमें पैरा-19 के तहत घरेलू उद्योग के मुद्दे पर चर्चा की गई है। प्राधिकारी ने पाया कि मैसर्स हरियाणा शीट ग्लास लि0, मैसर्स गुजरात बोरोसिल लि0 तथा मैसर्स आईएजी कं0 लि0 शीट ग्लास के विनिर्माता हैं। अन्य उत्पादक मैसर्स त्रिवेणी ग्लास लि0 को जो फ्लोट ग्लास के विनिर्माता हैं, याचिका में 'अन्य उत्पादकों' के तहत विनिर्माता दिखाया गया है। प्राधिकारी का विचार है कि मौजूदा जांच 'फ्लोट ग्लास' के संबंध में है और आयातक मैसर्स मोनिका ऐक्विजम और मैसर्स नवाकर इम्पेक्स प्रा0 लि0 की शीट ग्लास के विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के दायरे में शामिल करने संबंधी दलील तर्कसंगत नहीं है और न्यायोचित नहीं है। प्राधिकारी परावर्ती ग्लास को जांच के दायरे तथा उस पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने हेतु शामिल नहीं किए जाने के संबंध में घरेलू उद्योग के स्पष्टीकरण के अध्यक्षीन विचाराधीन उत्पाद संबंधी प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करता है। प्राधिकारी नोट करता है कि संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध माल तकनीकी तथा वाणिज्यिक दृष्टि से घरेलू उत्पादकों के उत्पाद का स्थानापन्न है। ऐसा हो सकता है कि घरेलू उत्पादकों द्वारा जांच-अवधि के दौरान कुछ मोटाई के फ्लोर ग्लास का उत्पादन नहीं किया गया हो। फिर भी, घरेलू उद्योग उसका उत्पादन करने में सक्षम है और आयातित संबद्ध माल घरेलू उत्पादित फ्लोट ग्लास का वाणिज्यिक स्थानापन्न है। आयातित संबद्ध माल गुण-धर्म घरेलू उत्पाद से मिलते हैं। समान वस्तु के मुद्दे पर किसी स्पष्ट दलील के अभाव में प्राधिकारी अपने इस विचार की पुष्टि करता है कि संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा फ्लोट ग्लास के समान वस्तु है।

9. जांच अवधि

वर्तमान जांच में जांच अवधि दिनांक 1 अप्रैल, 2001 से 31 दिसम्बर, 2001 तक है। आयातक मैसर्स मोनिका ऐक्विजिभ इंटरनेशनल लि० पुणे और मै० नवाकर इम्पेक्स प्रा० लि० ने तर्क दिया है कि गौण स्रोत के आयात आंकड़ों में परावर्ती ग्लास को भी शामिल किया गया है जो कि जांच में शामिल मद का हिस्सा है ही नहीं। परावर्ती ग्लास भी एचएस कोड 70.05 में आता है और इसे जांच आरंभ करने से पहले स्पष्ट तथा रंगीन फ्लोट ग्लास से अलग करना आवश्यक था। परावर्ती ग्लास को जांच के तहत मद से अलग नहीं किए जाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि आंकड़े सीमा शुल्क सदनों द्वारा शुल्क के भुगतान पर अधिकारिकतौर पर उपलब्ध कराए जाते हैं और इसलिए, गौण स्रोत के आंकड़ों पर निर्भर रहने से आशंका का आधार बनता है। प्रारंभन जुलाई, 2002 अर्थात् जांच-अवधि की अन्तिम तारीख के सात महीने बाद में किया गया। यह कहना हजम नहीं होता कि आंकड़े सात महीने बाद भी विश्वसनीय स्रोत से उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, यह दलील दी गई कि प्राधिकारी को समुचित विश्लेषण करने में जांच-अवधि की त्रैमासिकवार जानकारी सहायक हुई जबकि नौ महीनों की जांच अवधि संबंधी जानकारी की दो पूर्ण लेखा वर्षों से तुलना की गई है। प्राधिकारी का विचार है कि पाटनरोधी करार में जांच अवधि का निर्धारण नहीं किया गया है। किंतु, यह छः माह से कम भी नहीं होनी चाहिए। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि आयातकों ने उक्त दलील बहुत देर अर्थात् प्रकटन विवरण-पत्र के जारी होने के बाद प्रस्तुत की है। आयातक अथवा अन्य इच्छुक पक्षकार जांच-अवधि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के बारे में पूर्णतया अवगत था। फिर भी प्राधिकारी ने इस पहले की जांच की है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की याचिका का हवाला दिया जिसमें 'आयात आंकड़ों की मिलान-टिप्पणी' संलग्न थी। याचिकाकर्ता ने उक्त टिप्पणी में स्पष्ट रूप से कहा कि डीजीसीआई एण्ड एस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों में विभिन्न देशों से भारत में आयातित सभी प्रकार के फ्लोट ग्लास तथा समतल अथवा पालिशयुक्त ग्लास के मिश्रित ब्यौरे होते हैं। किन्तु, 'स्वच्छ और रंगीन किस्म के 2 एम एम से 12 एम एम (दोनों मोटाई शामिल) मोटाई के फ्लोट ग्लास (हरे ग्लास को छोड़कर) शामिल किन्तु सजावट, औद्योगिक अथवा आटोमोटिव प्रयोजनाथ्क्ष संसाधित ग्लास को छोड़कर' ग्लास जिनका पाटन किया जा रहा था और जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही थी, के बारे में थी। नोट आगे यह भी कहा गया कि याचिका में मात्र फ्लोट ग्लास को ही कवर करने को कहा गया जिसके लिए कोई शीर्षक नहीं दिया गया और न ही इस बारे में किसी एजेंसी (डीजीसीआईएण्डएस सहित) द्वारा कोई

आंकड़े ही संकलित किए जाते हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि इस तथ्य को देखते हुए कि डीजीसीआईएण्ड एस के संबद्ध माल के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे अतः उन्होंने इन्हें एकत्र किया और उन्हें इम्पेक्स डाटा सर्विसेज और बीई रजिस्टर से आईसीडी दिल्ली के लिए उपलब्ध आंकड़ों से मिलाया। प्राधिकारी को याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में दावा किए गए संबद्ध माल के आयात की मात्रा में परावर्ती ग्लास शामिल किए जाने की दलील में कोई तथ्य दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा, संबद्ध फ्लोट ग्लास की आयात-मात्रा भी निर्यातकों के प्रत्युत्तर से परिपुष्ट है। अतः प्राधिकारी यह समझता है कि इस मामले में जांच-अवधि समुचित है।

10. घरेलू उद्योग

मैसर्स टी.एल. वर्मा एण्ड कं० प्रा० लि० के विचारः

(i) भारत में घरेलू उद्योग कुल उत्पादन के प्रमुख अनुपात का दो याचिकाकर्ता कंपनियां प्रतिनिधित्व नहीं करती और इसलिए जांच रद्द कर दी जाए। दो उत्पादक और भी है अर्थात् (i) गुजरात गार्डियन लि०, और (2) मै० त्रिवेणी ग्लास लि०। इन दो उत्पादकों में से मै० गुजरात गार्डियन लि० ने याचिका का समर्थन किया है। मै० त्रिवेणी ग्लास लि० ने इस याचिका का समर्थन नहीं किया है।

(ii) याचिकाकर्ता जांच-अवधि के दौरान भारत में संबद्ध माल के कुल उत्पादन के 49.49% का भागीदार है। याचिकाकर्ता समर्थक विनिर्माता के साथ मिलकर भारत में संबद्ध माल के कुल घरेलू उत्पादन के 82.09% हिस्सा बनाते हैं।

(iii) प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के स्तर के संबंध में केवल दो याचिकाकर्ता कंपनियों ने विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है। समर्थन कंपनी ने प्राधिकारी का संगत ब्यौरे नहीं दिए हैं।

(iv) नियम 2(ख) के साथ पठित नियम 11(2) के अनुसार घरेलू उद्योग को हुई क्षति साबित होनी चाहिए जिसमें उन घरेलू उत्पादकों को कवर किया गया हो जिनका संबद्ध माल का सामूहिक उत्पादन भारत में उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख अनुपात बनाता हो। इस मामले में मात्र दो याचिकाकर्ता कंपनियों का कुल उत्पादन भारत में कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा नहीं बनता है। इस

प्रकार, नियम 12(ख) के अर्थ में याचिकाकर्ता कंपनियों को घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता ।

(v) नियम 5(3) के उपबंध में विहित 25% हिस्सेदारी संबंधी संभाव्य प्रावधान यहां लागू नहीं होता है । नियम 11 तथा अनुबंध-II में विहित मुहावरा 'घरेलू उद्योग' की व्याख्या नियम 2(ख) में प्रस्तुत परिभाषा के अनुसार की जाएगी । चूंकि नियम 2(ख) में प्रमुख अनुपात की जरूरत का उल्लेख है अतः यह आवश्यक है कि इन दोनों घरेलू उत्पादकों के लिए निर्धारित क्षति को नियम 11(2) में ही पूरा किया जाएगा, यदि वे प्रमुख अनुपात के परीक्षण में सफल हो जाएं । इस मामले में दोनों घरेलू उत्पादक प्रमुख अनुपात-परीक्षण में असफल रहे हैं । अतः क्षति-निर्धारण त्रुटियुक्त है और अनन्तिम शुल्क गैर-कानूनी है, अतः इसे वापस लिया जाना अपेक्षित है ।

(vi) अतः इस मामले में घरेलू उद्योग में तीन कंपनियों को कवर किया जाए अर्थात् दो याचिकाकर्ता कंपनियां - मै0 सेन्ट गोबिन ग्लास लि0 तथा मै0 फ्लोट ग्लास इण्डिया लि0 और समर्थक कंपनी मै0 गुजरात गार्डियन लि0 । दो याचिकाकर्ता कंपनियों के आंकड़े घरेलू उद्योग की स्थिति समझने हेतु पूरे नहीं होंगे।

(vii) चूंकि घरेलू उद्योग उसे हुई क्षति का पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा । इसलिए जांच को नियम 14(ख) के तहत रद्द कर दिया जाए ।

याचिकाकर्ता के विचार:

(i) हैक्समिन के मामले में इस मुद्दे पर प्राधिकारी के समक्ष दलील दी गई किन्तु उसे अस्वीकार किया गया और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह समझा कि घरेलू उद्योग हेतु क्षति-विश्लेषण तब भी किया जा सकता जब याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग का हिस्सा देश के उत्पादन के 50% से भी कम भी हो । इस मामले में पूरे क्षति-विश्लेषण में केवल दो ही याचिकाकर्ताओं संबंधी जानकारी पर ही विचार किया गया अपवाद केवल तब किया गया जब याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से और बिक्रियों का विश्लेषण किया गया जबकि अन्य उत्पादकों के बिक्री आंकड़ों पर विचार किया गया।

(ii) प्रस्तुत मामले में भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने बाजार हिस्से संबंधी करकों का विश्लेषण करते समय समूचे घरेलू उद्योग की जानकारी पर विचार किया न कि मात्र

याचिकाकर्ता की जानकारी पर । फ्लोट ग्लास के मामले में किया गया विश्लेषण निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विगत मामलों में लिए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है ।

(iii) आयातक के प्रतिनिधि ने उनके मामले के समर्थन में कोई प्राधिकार नहीं दिया कि मद ' प्रमुख अनुपात ' का आवश्यक रूप से अर्थ उनके लिए है जिनका घरेलू उत्पादन में 50% से भी अधिक हिस्सा हो ।

(iv) उपर्युक्त के प्रति बिना पूर्वाग्रह के आवेदन-पत्र भरते समय घरेलू उद्योग का दायित्व है कि वह याचिका दायर करने के प्रति ' बने रहने ' के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता तथा अन्य उत्पादकों संबंधी जानकारी प्रस्तुत करें । इस स्थिति में अन्य उत्पादकों के संबंध में जानकारी याचिकाकर्ता द्वारा सर्वोत्तम उपलब्ध स्रोतों से एकत्र की जाती है । हमने अब गैर-याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादकों से प्रमाणित जानकारी एकत्र की जाती है । हमने अब गैर-याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादकों से प्रमाणित जानकारी एकत्र की है जिसमें यह इंगित है कि याचिकाकर्ताओं का उत्पादन के 50% से भी अधिक हिस्सा है जैसाकि नीचे सारणी में दिया गया है:-

याचिकाकर्ता	जांच अवधि	
	मात्रा(एमटी)	रु० (लाख)
फ्लोटग्लास इंडिया लि०	96122	15541
सेंट-गोबिन ग्लास इंडिया लि०	95641	15743
याचिकाकर्ताओं का योग	191763	31284
समर्थक उत्पादक		
गुजरात गार्डियन लि०	107441	19456
समर्थक उत्पादकों का योग	107441	19456
अन्य उत्पादक		
त्रिवेणी ग्लास लि०	51060	7713
कुल योग	350264	58453
याचिकाकर्ताओं का %	54.75%	
याचिकाकर्ताओं तथा समर्थकों का %	85.42%	

(V) उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं का हिस्सा समान वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन का 54.75% है।

मै० टी.एल. वर्मा कं० प्रा० लि० ने प्रकटन विवरण-पत्र के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित विचार व्यक्त किये हैं

(i) याचिकाकर्ता कंपनियों को चाहिए था कि वे आवेदन करते समय 'घरेलू उद्योग' के रूप में अपनी स्थिति सिद्ध करते। उनके पास प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दोनों याचिकाकर्ता कंपनियों का सामूहिक उत्पादन 50% से भी कम था। ऐसा प्रारंभिक निष्कर्षों से विदित है। याचिकाकर्ता अचानक लिखित निवेदन में कुछ ऐसे नए आंकड़े देता है कि गैर-याचिकाकर्ता कंपनियों का हिस्सा कुल घरेलू उत्पादन के 50% से भी अधिक हो जाता है। यह दावा तथ्यों पर आधारित नहीं है। संशोधित आंकड़े भी वास्तविक उत्पादन नहीं बल्कि वाषिर्कीकृत उत्पादन दर्शाते हैं।

(ii) याचिकाकर्ता का दायित्व यह था कि वह याचिका दायर करते समय सही ब्यौरे प्रस्तुत करता ताकि यथोचित शंका से परे यह बात साबित हो जाती कि वे पूर्व निर्धारित मानदण्ड पूरा करता है।

(iii) हैक्सामिन मामले में प्राधिकारी की कार्रवाई न्यायिक दृष्टि से प्रमाणित नहीं रही। नियम 11(2) के अनुसार, प्राधिकारी से अपेक्षा है कि घरेलू उद्योग संबंधी क्षति का मूल्यांकन करे। नियम 2(ख) के अनुसार, घरेलू उद्योग का अर्थ है-सभी घरेलू उत्पादक अथवा ऐसे उत्पादक जिनका सामूहिक उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन के प्रमुख भाग को दर्शाता हो। अतः कानूनी दृष्टि से प्राधिकारी पर बंधन है कि वह ऐसे घरेलू उत्पादकों के संबंध में क्षति का मूल्यांकन करे जिनका उत्पादन प्रमुख अनुपात परीक्षण में सफल रहा हो।

(iv) प्राधिकारी ने गैर-याचिका कंपनियों की उत्पादन मात्रा बिना किसी पड़ताल के स्वीकार कर ली। इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि कार्रवाई में अन्तिम चरण में आंकड़ों में संशोधन क्यों और किस आधार पर किया गया। नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी से अपेक्षा है कि वह इच्छुक पक्षकारों द्वारा दी गई जानकारी जिस पर निष्कर्ष आधारित हैं, की शुद्धता के प्रति सन्तुष्ट हो जाए।

मै0 मोनिका ऐक्सिम इंटरनेशनल लि0 और मै0 नवाकर इम्पेक्स प्रा0 लि0 की टिप्पणियाँ

याचिकाकर्ताओं ने त्रिवेणी फ्लोट ग्लास, इण्डियन शीट के उत्पाद और आयातित ग्लास का समान वस्तु मान लिया जाए यदि याचिकाकर्ता आयातित ग्लास को अपने फ्लोट ग्लास से समान उत्पाद समझते हैं। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इसे स्वीकार करें तो याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की परिभाषा में नहीं आते हैं क्योंकि वे कुल भारतीय उत्पादन के प्रमुख हिस्से का प्रतिनिधित्व नहीं करते। अब भी याचिकाकर्ता प्रमुख हिस्से से नीचे स्तर पर हैं। प्रकटन विवरण-पत्र में प्राधिकारी ने यह कहते हुए प्रारंभिक निष्कर्षों में लिए गए पिछले रूख में परिवर्तन कर दिया है कि याचिकाकर्ता का हिस्सा 54.75% है न कि 49.49% जैसा कि पहले बताया गया था। प्राधिकारी से अपेक्षा है कि वह जांच आरंभ करते समय विश्वसनीय आंकड़ों का खुलासा करें।

प्राधिकारी द्वारा जांच:

प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के मुद्दे पर विभिन्न दलीलों की जांच की है। याचिकाकर्ता ने अन्य दो घरेलू उत्पादकों - मै0 गुजरात गार्डियन लि0 तथा मै0 त्रिवेणी ग्लास लि0 से भी पत्र प्रस्तुत किए हैं। दोनों कंपनियों ने अप्रैल-दिसंबर, 2001 की अवधि के लिए संबद्ध माल के अपने-अपने उत्पादन की निम्नानुसार पुष्टि की है -

मै0 गुजरात गार्डियन लि0	107441 एम.टी
मै0 त्रिवेणी ग्लास लि0	51060 एम.टी

प्राधिकारी ने भी जांच की कि उपर्युक्त उत्पादन-आंकड़े अप्रैल-दिसम्बर, 2001 की अवधि के लिए हैं न कि वार्षिकीकृत जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने सार्वजनिक सुनवाई के बाद अपने दिनांक 3.3.2003 के पत्र में गलती से उल्लेख किया था। जांच-अवधि अप्रैल-दिसं0, 2001 के लिए चारों उत्पादकों के संबद्ध माल का कुल उत्पादन 350264 एमटी रहा। इसमें से दो याचिकाकर्ता कंपनियों अर्थात् मै0 फ्लोट ग्लास इण्डिया लि0 और मै0 सेंट गोबिन ग्लास इण्डिया लि0 का हिस्सा 191763 एम टी है। यह कुल उत्पादन का 54.75% बैठता है। प्राधिकारी का विचार है कि उपर्युक्त दोनों गैर-याचिकाकर्ता कंपनियों ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध माल के अपने उत्पादन के बारे में लिखित रूप में पुष्टि कर दी है। प्राधिकारी उसे ही सही समझता है। फिर भी, याचिका संबद्ध माल के उन उत्पादकों का

समर्थन प्राप्त हुआ जिनका प्रारंभन के समय भी घरेलू उत्पादन 50% से भी अधिक हिस्सा था। चूंकि दानों याचिकाकर्ता कंपनियों अर्थात् मै0 फ्लोट ग्लास इण्डिया लि0 और मै0 सेंट गोबेन ग्लास इण्डिया लि0 का हिस्सा कुल उत्पादन के 54.75% है अतः वे संबद्ध माल के कुल घरेलू उत्पादन के प्रमुख हिस्से के प्रतिनिधि हैं। प्राधिकारी समझता है कि ये दो याचिकाकर्ता कंपनियां नियम 2(ख) और नियम 11(2) के अर्थ में घरेलू उद्योग की प्रतिनिधि हैं। संबद्ध माल की कुल मांग तथा निबल बिक्री-आय के कारकों के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने समर्थक उत्पादक मै0 गुजरात गार्डियन लि0 से संबंधित जानकारी पर विचार किया।

11. अगोपनीय जानकारी प्रस्तुत करना:

मै0 टी एल वर्मा एण्ड कं0 प्रा0 लि0 के विचार:

मोटाई के अभाव में वर्गमीटर से एमटी में मात्रा को परिवर्तित करने में अपनाई जाने वाली पद्धति के संबंध में निष्कर्षों में उल्लिखित आयात आंकड़ों के मिलान संबंधी टिप्पणी में कोई उल्लेख नहीं है। इम्पेक्स स्टेटिस्टिक्स सर्विसेज द्वारा प्रकाशित आयात आंकड़ों में सभी सौदों में "मोटाई" के ब्यौरे नहीं हैं। आयात-मात्रा के निर्धारण में यह एक अहम तत्व होता है। अतः विरोधी इच्छुक पक्षकारों को यह जानने का अधिकार है कि आंकड़ों में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ। हमने वर्गमीटर को एम टी में परिवर्तन करने में प्रयुक्त मानदण्ड और उसके आधार को प्रकट करने हेतु उनसे कहा था। इसके अलावा, प्रपत्र- 4 क (आयात आंकड़ों संबंधी मद-1 को छोड़कर), लाभ संबंधी सारणी, बिक्री मात्रा, बिक्री लागत, यूनिट कीमत तथा हानि अथवा लाभ, पूंजी निवेश पर आय, कम बिक्री कीमत, कम कीमत तथा प्रपत्र 4 ख के संबंध में याचिका के अगोपनीय भाग में कुछ भी नहीं दिया गया है।

प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के संबंध में एनआईपी तथा क्षति मार्जिन के निर्धारण में अपनाए गए आधार एवं पद्धति का खुलासा नहीं किया है।

इण्डोनेशिया सरकार के विचार:

अधिसूचना में प्रयुक्त गोपनीयता स्तर करार के अनुच्छेद 6.5 की जरूरतों के मद्देनजर अनुचित है। पाटित आयातों का कीमत-प्रभाव उस कीमत कम-निर्धारण में स्पष्टतया महत्वपूर्ण है। इसका तथा-कथित परिणाम है कि कीमत में गिरावट आई है। किन्तु,

आधारिक कीमत-जानकारी का कोई पर्याप्त अगोपनीय सारांश नहीं दिया गया है। कम से कम, जानकारी सूची तथा % रूप में प्रदान की जानी चाहिए ताकि जांच अधिकारी द्वारा की जा रही जांच प्रमाणित हो सके।

याचिकाकर्ता के विचार

- (i) हमें इस तथ्य की चिन्ता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस तथ्य के बावजूद पी.टी. मूलिया द्वारा प्रस्तुत जानकारी स्वीकार की है कि उन्होंने अपने प्रत्युत्तर का अगोपनीय हिस्सा नहीं दिया है। इस तरह वे अपने कानूनी दायित्व को पूरा करने में असफल रहे हैं। इस संबंध में प्रारंभिक निष्कर्षों का पैरा-5(i) देखें।
- (ii) पक्षकारों ने अपने निवेदन में हमारे द्वारा प्रस्तुत अगोपनीय हिस्से की अपर्याप्तता के बारे में आपत्ति उठाते हुए कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। उन्होंने आयातक की जो प्रश्नावली के साथ अनुलग्नक प्रस्तुत किए वे या तो बिल्कुल खाली थे अथवा उनमें यह स्वीकृति शामिल थी कि सारांशीकरण के लिए जानकारी भावुक नहीं है क्योंकि जानकारी बिल्कुल संवेदनशील है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

- (i) जहां तक निर्यातक मैसर्स पी टी मूलिया ग्लास द्वारा प्रस्तुत अगोपनीय हिस्से का संबंध है वह निर्यातक ने प्रस्तुत कर दी थी और उसे सार्वजनिक फाइल में रख दिया गया है। निर्यातक मैसर्स इम्पेक्ट सेफ्टी ग्लास वर्क्स प्रा० लि० ने आयातक प्रश्नावली का कोई अगोपनीय हिस्सा प्रस्तुत नहीं किया जिसे प्रारंभिक निष्कर्ष के पैरा 11 में रिकार्ड किया गया। उक्त आयातक ने सार्वजनिक सुनवाई के बाद विस्तृत टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। प्राधिकारी ने उनके सामान्य निवेदन पर विचार किया है जहां अगोपनीय हिस्सा प्रस्तुत किया गया है।
- (ii) जहां तक प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के संबंध में एन आई पी और क्षति मार्जिन के निर्धारण में अपनाई गई पद्धति संबंधी अप्रकटीकरण के बारे में आयातक की दलील का संबंध है, प्राधिकारी ने सतत पद्धति का अनुसरण किया है जिसके तहत घरेलू उद्योग के संबंध में एन आई पी के निर्धारण संबंधी पद्धति घरेलू उद्योग को गोपनीय आधार पर सूचित की गई है।

प्रकटीकरण विवरणपत्र के इस भाग में घरेलू उद्योग के लिए अहानिकर कीमत शामिल है जो उत्पादन लागत संबंधी गोपनीय जानकारी पर आधारित है ।

- (iii) जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा अपर्याप्त अगोपनीय हिस्से को प्रस्तुत नहीं किए जाने की बात है, प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्ष के पैरा 21 को स्मरण करता है। एक आयातक द्वारा यह दलील दी गई थी कि वर्गमीटर को मी.टन में मात्रा परिवर्तित करने में अपनाई गई पद्धति का खुलासा नहीं किया है । यह जानकारी निर्यातक मैसर्स पी टी मूलिया तथा याचिकाकर्ता द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी में शामिल है । प्राधिकारी इसे गोपनीय मानता है और उसकी राय है कि इसका खुलासा करना आवश्यक नहीं है । याचिकाकर्ता ने आयात तथा घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, बिक्री मूल्य, यूनिट कीमत, माल सूची संबंधी आयात तथा सूचीबद्ध जानकारी संबंधी अगोपनीय हिस्से के पैरा IV में जानकारी प्रस्तुत की । याचिकाकर्ता ने लाभप्रदता, पूंजी निवेश पर आय, कम कीमत के आंकड़े तथा कीमत कम करने संबंधी आंकड़े, आयातों के बंदरगाह पर उतारते समय के मूल्य से संबंधित जानकारी के बारे में गोपनीयता का दावा किया है । प्राधिकारी का विचार है कि उक्त सूचना जिसे गोपनीय माना जा रहा है वह याचिकाकर्ता के कार्यनीति व्यवसाय के हित में है और ऐसा समझता है कि इसे नियम 7(1) के अनुसार गोपनीय समझा जाए ।

ग. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन संबंधी दावों की जांच

12. जैसा कि प्रारंभिक निष्कर्षों में प्रस्तुत किया गया है, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में संबद्ध माल के ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी । निम्नलिखित निर्यातकों से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए:-

- (i) पी टी मूलिया ग्लास, इंडोनेशिया
- (ii) पी टी आब्दी राक्यात बक्ती, इंडोनेशिया
- (iii) पी टी टेंसिण्डो, इंडोनेशिया
- (iv) मैसर्स किनहूंग्दाओ हुआजोऊ ग्लास कं० लि०, चीन
- (v) मैसर्स ननिंग फ्लोट ग्लास कं० लि०, चीन

प्रारंभिक निष्कर्षों के बाद संबद्ध देशों के विभिन्न इच्छुक पक्षकारों/सरकारों से निम्नलिखित दलीलें प्राप्त हुई हैं :-

13. इंडोनेशिया गणराज्य सरकार के निवेदन

आवेदन पत्र में प्रयुक्त सामान्य मूल्य के लिए आधार - पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.2 के अनुसार, आवेदन-पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ पाटन का साक्ष्य शामिल होना चाहिए और वह संगत साक्ष्य द्वारा पुष्ट सामान्य स्वीकृति पर आधारित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, इस करार के अनुच्छेद 5.2 के अनुसार प्राधिकारी आवेदन-पत्र में प्रस्तुत साक्ष्य की शुद्धता तथा पर्याप्तता की जांच करेगा ताकि इस बात का निर्धारण हो सके कि क्या जांच आरंभ करने के औचित्य का पर्याप्त साक्ष्य है या नहीं। इस संबंध में पी टी मूलिया इंडोनेशिया के वार्षिक लेखे समुचित आधार नहीं है जिससे संबद्ध माल की उत्पादन लागत का मूल्यांकन किया जा सके क्योंकि मूलिया ग्लास की धारक कंपनी विविध उत्पादों की लंबी श्रृंखला का उत्पादन करती है।

14. मै0 पी टी मूलिया ग्लास के निवेदन

(i) पैकिंग, समुद्री भाड़े, बीमा, नौवहन प्रभार, ट्रकिंग लागत, क्लीयरेंस तथा हैंडलिंग और धूम्रीकरण प्रभारों संबंधी लेखाओं के समायोजन निर्यात कीमत में समाविष्ट किए गए हैं। किन्तु फैक्टरी से माल निकालते समय की निर्यात कीमत की गणना करते समय प्राधिकारी ने निर्णय लिया कि किसी भी मोटाई तथा रंग के भारित औसत को अपनाया जाए। हमने जांच अवधि के दौरान भारत को 2 एम एम तथा 3 एमएम मोटाई के फ्लोट ग्लास का निर्यात नहीं किया है। अधिकांश निर्यात में 12 एम एम *** मी.टन, 4 एम एम डार्क ग्रे *** मी.टन तथा 5 एम एम *** मी.टन शामिल हैं। फैक्ट्री से निकालते समय की निर्यात कीमत के भारित औसत की गणना करते समय प्राधिकारी को चाहिए कि वह स्पष्ट तथा रंगीन/रंगीन फ्लोट ग्लास में अंतर करें।

(ii) हम प्राधिकारी की 2 एम एम से 12 एम एम मोटाई के फ्लोट ग्लास के सभी आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क संबंधी सिफारिश से सहमत नहीं हैं। जिस मोटाई का जांच अवधि के दौरान भारत को

निर्यात नहीं किया गया अर्थात् 2 एम एम तथा 3 एम एम, उसे पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से बाहर रखा जाए ।

(iii) इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि भारत को होने वाले हमारे निर्यात पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए जब तक कि अंतिम निर्णय नहीं हो जाता । ऐसा शुल्क लगाए जाने का निर्णय तभी लिया जाना चाहिए जब हमारी प्रस्तुत जानकारी की पड़ताल नहीं हो जाती तथा उस पर हमारे विचार नहीं लिए जाते ।

(iv) चीन से उपयुक्त रूप में वहां के निर्यातकों से पूर्ण प्रत्युत्तर के अभाव में प्राधिकारी ने अनुकूल कुशलता स्तर पर सामान्यीकृत करने के बाद भारत के घरेलू उद्योग की वास्तविक उत्पादन लागत के आधार पर चीन के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है । हमने इच्छुक होकर और अनुकूल विश्वास में जांच में हिस्सा लिया है और इसलिए पी टी मूलिया ग्लास के संबंध में ऐसा ही मानक लागू करके प्राधिकारी सामान्य मूल्य का निर्धारण करे जो चीन के संबंध में उल्लिखित मूल्य से अपेक्षतया कम है ।

15. मैसर्स इम्पैक्ट सेफ्टी ग्लास वर्क्स लि० बंगलौर के निवेदन

(i) असाही के इंडोनेशिया में फ्लोट ग्लास के तीन संयंत्र हैं और इनका इंडोनेशिया में 1/3 उत्पादन हिस्सा है । जब उनके समस्तर कंपनी इंडोनेशिया में माल बेच रही है तो यह बात उचित नहीं है कि उत्पादन की कृत्रिम लागत को नहीं अपनाया जाना चाहिए । उत्पादन की कृत्रिम लागत के संबंध में भी याचिकाकर्ता ने मूलिया इंडस्ट्रीज की वार्षिक रिपोर्ट का उपयोग किया है जबकि वह एक उत्पादक नहीं है बल्कि एक धारक कंपनी है जिसकी बहुत सी अनुषंगी फैक्ट्रियां तथा कंपनियां हैं । मूलिया इंडस्ट्रीज के तुलन-पत्र पर आधारित उत्पादन लागत की गणना करना प्राधिकारी को भ्रमित करना है ताकि अनंतिम शुल्कों को लगाए जाने में लाभ लिया जाए ।

(ii) निर्यात कीमत से किए गए समायोजन का खुलासा नहीं किया गया है। समुद्री भाड़े तथा अन्य प्रभारों संबंधी जानकारी का खुलासा इस मामले में एम आर टी पी तथा सर्वोच्च न्यायालय के सामने अगोपनीय

आधार पर किया गया है। अब वही जानकारी गोपनीय कैसे हो जाती है। पाटन मार्जिन की राशि का खुलासा नहीं किया गया है।

16. घरेलू उद्योग के विचार

इंडोनेशिया के निर्यातकों के खिलाफ उन पर अन्य प्राधिकारियों द्वारा पाटनरोधी कई मामले दायर किए गए हैं। ऐसा लगता है कि पाटन कीमतों पर सप्लाई करना उनकी नीति है जिससे घरेलू उद्योग के हितों को भारी क्षति हो सके।

प्राधिकारी द्वारा जांच

17. इंडोनेशिया के सामान्य मूल्य

इंडोनेशिया के निम्नलिखित निर्यातकों ने जांच का प्रत्युत्तर भेजा है:-

- (i) पीटी मूलिया ग्लास, इंडोनेशिया
- (ii) पीटी आब्दी राक्यात बक्ती, इंडोनेशिया
- (iii) पीटी टेंसिण्डो, इंडोनेशिया

इंडोनेशिया सरकार तथा कुछ अन्य आयातकों ने यह दलील दी है कि याचिका में दी गई जानकारी प्राक्कलन पर आधारित थी और मूलिया इंडट्रिंडो के तुलन-पत्र पर पीटी मूलिया के सामान्य मूल्य निर्धारण का आधार गलत था। प्राधिकारी का विचार है कि जांच आरंभ करते समय याचिका में तथाकथित पाटन के दावे के समर्थन में सामान्य मूल्य प्राक्कलन संबंधी प्रथमदृष्टया जानकारी शामिल होनी चाहिए। किंतु प्राधिकारी को मैसर्स पी टी मूलिया से प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ था और प्रारंभिक निष्कर्षों के स्तर पर भी इंडोनेशियाई निर्यातकों के सामान्य मूल्य का निर्धारण उक्त निर्यातक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर किया गया। इस प्रकार प्राधिकारी को इस संबंध में इंडोनेशियाई सरकार तथा आयातकों की दलील में कोई गुणावगुण दिखाई नहीं देता है।

18. पीटी मूलिया ग्लास, इंडोनेशिया

प्राधिकारी को पाटन के मुद्दे पर प्रारंभिक निष्कर्षों का स्मरण आता है। मैसर्स पीटी मूलिया ग्लास ने घरेलू बिक्री, भारत को निर्यात, उत्पादन लागत, निर्यात तथा घरेलू बिक्री संबंधी बिक्री कीमत निर्धारण से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की थी। प्राधिकारी ने निर्यातक की जानकारी की मौके पर पड़ताल भी की है। प्राधिकारी ने मैसर्स पीटी मूलिया ग्लास द्वारा उत्पादित संबद्ध माल की उत्पादन लागत की पड़ताल की है। पैकिंग, अंतरदेशीय भाड़े, छूट, ऋण आदि संबंधी समायोजनों की भी पड़ताल की गई। जहां तक अंतरदेशीय भाड़े (ट्रकिंग) का संबंध है निर्यातक इंडोनेशिया के विभिन्न हिस्सों में घरेलू बिक्री करता है जिसमें स्थान के अनुसार अलग-अलग भाड़ा लागत होती है। प्रत्येक क्षेत्र को की गई घरेलू बिक्री की मात्रा तथा प्रत्येक क्षेत्र की भारित औसत भाड़ा लागत के आधार पर निर्यातक ने इंडो-रूपयाह *** पीएमटी की भारित औसत भाड़ा लागत प्रस्तुत की है जिसे घरेलू बिक्री कीमत से समायोजन हेतु स्वीकार किया गया है। निर्यातक ने घरेलू बिक्रियों पर दिए गए ऋण संबंधी जानकारी भी प्रस्तुत की है। प्राधिकारी ने इसे भी स्वीकार कर लिया। अलग-अलग मोटाई की घरेलू बिक्री कीमत के विश्लेषण से इंगित होता है कि अधिकांश घरेलू बिक्री सामान्य व्यापार के रूप में हुई है। बिक्री के 20% से अधिक 4 एम एम मोटाई(स्पष्ट) के मामले में सामान्य व्यापार नहीं है अर्थात् इसमें उत्पादन लागत जमा बिक्री, प्रशासन तथा सामान्य लागत शामिल है। शेष *** % लाभार्जन बिक्री को सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए लिया गया है। अतः प्राधिकारी ने निर्यातक के फैक्ट्री से निकलते समय की कीमत को घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर अलग-अलग मोटाई के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। जहां तक निर्यातक की इस दलील का संबंध है कि चीन के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण भारतीय घरेलू उद्योग पर आधारित उत्पादन की कृत्रिम लागत के आधार पर किया गया है, प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

19. पीटी अब्दी राक्यात बक्ती, इंडोनेशिया

प्राधिकारी को पाटन के मुद्दे के संबंध में प्रारंभिक निष्कर्षों का स्मरण आता है। निर्यातक ने गोपनीय चिह्नित सभी जानकारी का केवल एक सैट उत्तर प्रस्तुत किया है। अगोपनीय जानकारी का कोई और सैट प्रस्तुत नहीं किया है जैसाकि नियम 7(2) के तहत अपेक्षित है। निर्यातक को दिनांक 6.9.2002 के पत्र द्वारा यह भी सलाह दी गई थी कि वे प्रस्तुत नहीं किए गए अगोपनीय हिस्से को भी प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने पाया है कि निर्यातक ने अगोपनीय हिस्सा प्रस्तुत नहीं करने का

संतोषजनक कारण नहीं बताया है। निर्यातक ने उत्पादन लागत और लाभ/हानि लेखा सञ्चा तुलन-पत्र संबंधी जानकारी भी प्रस्तुत नहीं की। प्राधिकारी नोट करता है कि निर्यातक ने प्रारंभिक निष्कर्षों के बाद कोई टिप्पणी अथवा जानकारी नहीं भेजी है। इस प्रकार प्राधिकारी निर्णय देता है कि निर्यातक ने जांच में पूर्णतया सहयोग नहीं दिया है। अतः प्राधिकारी निर्यातक द्वारा नियम 7(3) के अनुसार प्रस्तुत जानकारी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए प्राधिकारी सामान्य मूल्य निर्णयन के लिए नियम 6(8) के तहत सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी पर विश्वास करने को बाध्य है। प्राधिकारी ने इस निर्यातक के बारे में मैसर्स पी टी मूलिया ग्लास, इंडोनेशिया के मामले में उपलब्ध जानकारी के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

20. पीटी टेंसिण्डो, इंडोनेशिया

प्राधिकारी को पाटन संबंधी मुद्दे पर प्रारंभिक निष्कर्षों का स्मरण आता है। मैसर्स पीटी टेंसिण्डो, इंडोनेशिया द्वारा प्रस्तुत जानकारी पूर्णतया अपूर्ण पायी गई। निर्यातक ने जैसाकि प्रारंभिक निष्कर्षों में उल्लेख किया गया, अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। अतः प्राधिकारी सामान्य मूल्य निर्णयन के संबंध में सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी पर विश्वास करने को बाध्य हैं। अतः प्राधिकारी ने निर्यातक के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण मै0 पी टी मूलिया ग्लास, इंडोनेशिया के संबंध में उपलब्ध जानकारी के आधार पर कर दिया है।

21. इंडोनेशिया के संबंध में निर्यात कीमत

प्राधिकारी को निर्यात कीमत निर्धारण के संबंध में प्रारंभिक निष्कर्षों का स्मरण है। मैसर्स पी टी मूलिया ग्लास के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण निर्यातक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर किया गया है। उन्होंने अलग-अलग मोटाई के फ्लोट ग्लास 'स्पष्ट' तथा 'डार्क ग्रे' के निर्यात के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकारी ने प्रश्नावली के प्रत्युत्तर में दिखाई गई निर्यात कीमत पर विचार किया है। निर्यातक ने पैकिंग, समुद्री भाड़े, बीमा, नौवहन प्रभार, ट्रकिंग लागत, क्लीयरेंस तथा हैंडलिंग और धूसीकरण प्रभारों के संबंध में समायोजन दिखाए हैं। प्राधिकारी ने इन समायोजनों संबंधी जानकारी की पड़ताल की है। समुद्री भाड़ा समायोजन पर पड़ताल के दौरान निर्यातक द्वारा प्रस्तुत विवरण-पत्र के अनुसार वास्तविक आधार पर किया गया है। फैक्ट्री से निकलते समय की निर्यात कीमत का निर्धारण उपर्युक्त समायोजनों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

22. मै0 पीटी टेसिंडों के संबंध में निर्यात कीमत पर विचार भारत को की गई बिक्रियों की प्रस्तुत जानकारी के आधार पर किया गया । प्रारंभिक निष्कर्षों के बाद निर्यातक से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । मै0 पीटी मूलिया के मामले में उपलब्ध जानकारी के आधार पर समायोजन सी आई एफ निर्यात कीमत के आधार पर किया गया है ताकि निर्यात कीमत की फैक्ट्री से माल निकालते समय की कीमत का निर्धारण किया जा सके ।

23. पीटी आब्दी राक्यात बक्ती, इंडोनेशिया के संबंध में निर्यात कीमत पर भारत को की गई बिक्रियों के संबंध में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर विचार किया गया । निर्यातक से प्रारंभिक निष्कर्षों के बाद कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । मैसर्स पीटी मूलिया के मामले में उपलब्ध जानकारी के आधार पर समायोजन सी आई एफ निर्यात कीमत के आधार पर किया गया है ताकि निर्यात कीमत की फैक्ट्री से माल निकालते समय की कीमत का निर्धारण किया जा सके ।

24. चीन जनवादी गणराज्य के संबंध में सामान्य मूल्य

प्राधिकारी को पाटन के मुद्दे के संबंध में प्रारंभिक निष्कर्षों का स्मरण है । चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी निर्यातक ने उन्हें भेजी गई प्रश्नावली का पूर्णतया उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है । मै0 किन्हूआंगदो हुआजुओ ग्लास कं0 लि0, चीन जिन्होंने बताया कि उन्होंने संबद्ध माल का जांच अवधि के दौरान निर्यात किया है, ने प्रश्नावली के अनुसार जानकारी प्रस्तुत नहीं करके सहयोग नहीं किया । अन्य निर्यातक मैसर्स ननिंग फ्लोट ग्लास कं0 लि0, चीन ने सूचित किया कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान निर्यात नहीं किया है और इसलिए उन्होंने प्रश्नावली का उत्तर ठीक से नहीं भरा है । जहां तक आयातक का पीटी मूलिया इंडोनेशिया के संबंध में सामान्य मूल्य अपनाने की दलील का संबंध है जिससे कि चीन के उत्पादकों के सामान्य मूल्य का निर्धारण हो सके, प्राधिकारी को इस दलील में कोई गुणावगुण नहीं मिला है क्योंकि वह पाटनरोधी नियमावली के अनुरूप नहीं है । इंडोनेशियाई निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण उस देश की घरेलू बिक्री के आधार पर किया गया है । चीन के किसी भी निर्यातक से पूर्ण जानकारी के अभाव में प्राधिकारी ने चीन के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है । अतः प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों से निर्धारित रूप तथा तरीके में पूर्ण जानकारी के

अभाव की पुष्टि करता है जिससे उपर्युक्त नियम 6(8) के अनुसार उसे उपलब्ध तथ्यों के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य से निर्यात के संबंध में निष्कर्ष दिए जा सकें। तदनुसार प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन की कृत्रिम लागत के आधार पर किया है। ऐसा करते समय प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत उत्पादन लागत संबंधी साक्ष्य को स्वीकार किया है और अनुकूल दक्षता स्तर पर सामान्यीकृत करके घरेलू उद्योग की वास्तविक उत्पादन लागत के संदर्भ में सामान्य मूल्य का हवाला दिया है।

इंडोनेशिया के अन्य निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत

25. अन्य असहयोगी निर्यातकों के संबंध में प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण सहयोगकर्ता निर्यातक की घरेलू बिक्री कीमत के साक्ष्य के आधार पर किया है। न्यूनतम निर्यात कीमत को सहयोगकर्ता निर्यातक की इस कीमत के रूप में स्वीकार किया गया।

पाटन मार्जिन

26. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक 1 में विहित अनुसार सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण संबंधी सिद्धांतों को अपनाई जाने वाली सतत् पद्धति का अनुसरण किया है। पाटन मार्जिन का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 6 में विहित सिद्धांतों के अनुसरण में निर्यात कीमत की सामान्य मूल्य से उचित तुलना करके किया गया है। यह तुलना व्यापार के उसी स्तर पर अर्थात् फैक्ट्री से निकालते समय की कीमत के बराबर है। जहां तक अलग-अलग मोटाई के स्पष्ट तथा रंगीन फ्लोट ग्लास के सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत की उचित तुलना के संबंध में कुछ इच्छुक पक्षकारों द्वारा व्यक्त चिंता का संबंध है, प्राधिकारी ने उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अलग-अलग मोटाई तथा रंग के फ्लोट ग्लास की निर्यात कीमत तथा सामान्य मूल्य में अंतर करके ध्यान दिया है। जहां तक निर्यातकों द्वारा इंडोनेशिया के निर्यातकों के संबंध में भिन्न-भिन्न पाटन मार्जिन के संबंध में दी गई दलील का संबंध है, जब कि सामान्य मूल्य उसी स्तर पर है, प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन का निर्धारण करते समय अलग-अलग निर्यातक की निर्यात कीमत को ध्यान में लिया है। भारत और पाटन मार्जिन का निर्धारण अलग-अलग मोटाई/रंग के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के

बाद किया गया है। सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के उपर्युक्त निर्धारण के आधार पर प्राधिकारी ने निम्नलिखित पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है(%):

क्र. सं.	देश	निर्यातक का नाम	पाटन मार्जिन %
1.	इंडोनेशिया	मै0 पीटी मूलिया	46.71
2.	इंडोनेशिया	मै0 पीटी टेंसिण्डो	54.63
3.	इंडोनेशिया	मै0 पीटी आब्दी राक्यात बक्ती	78.91
4.	इंडोनेशिया	सभी अन्य निर्यात	78.91
5.	चीन	सभी निर्यातक	43.82

घ. क्षति तथा क्षति की आशंका

27. पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में निम्नानुसार व्यवस्था है:
'क्षति का निर्धारण'

(1) निर्दिष्ट देशों से हुए आयातों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी आगे अपने निष्कर्ष दर्ज करेंगे कि भारत में होने वाले ऐसे आयातों से भारत में स्थापित किसी उद्योग को वास्तविक क्षति होती है अथवा क्षति का खतरा उत्पन्न होता है अथवा किसी उद्योग को स्थापित करने में बाधा आती है,

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के खतरे और घरेलू उद्योग की स्थापना में आने वाली वास्तविक बाधा और पाटित आयातों की मात्रा, और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर इसके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव समेत सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इन नियमों के अनुबंध II में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का मूल्यांकन करेंगे।'

28. पाटनरोधी नियमों के अनुबंध II में क्षति के निर्धारण संबंधी सिद्धांतों में यह प्रावधान है कि:

क. क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा तथा समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव दोनों की वस्तुपरक जांच शामिल होगी।

ख. पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। नियम 18 के उपनियम(2) में यथा उल्लिखित कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा अत्याधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा काफी हद तक कीमतों में कमी लाना अथवा कीमत में उस वृद्धि को रोकना है जो कि अन्यथा काफी हद तक बढ़ गई होती।

29. इंडोनेशिया गणराज्य सरकार के निवेदन

(i) प्रारंभिक निष्कर्षों संबंधी अधिसूचना में तथ्यों एवं कानून के मामले शामिल होने चाहिए जिनके आधार पर दलीलों को स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाता है। चूंकि जांच अवधि के दौरान बिक्री मात्रा एवं बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है इसलिए रोकड़ प्रवाह सकारात्मक होना चाहिए था न कि नकारात्मक, जैसाकि दावा किया गया है।

(ii) क्षति का निर्धारण सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए और इसमें घरेलू बाजार की कीमतों पर पाटित आयातों की मात्रा और उसके प्रभाव की जांच का उद्देश्य शामिल होना चाहिए। तथाकथित पाटित आयातों में गिरावट हुई है। प्राधिकारी के निष्कर्षों की जांच की पुनरीक्षा होनी चाहिए। आयातों में अति वृद्धि नहीं हुई है जैसाकि प्राधिकारी ने अपने निष्कर्षों में दर्शाया है।

(iii) प्राधिकारी इस बात की पुनः जांच करें कि क्या आयातों में मांग अथवा उत्पादन की तुलना में वृद्धि हुई है।

(iv) क्षति से संबंधित सभी कारकों का मूल्यांकन होना चाहिए। प्राधिकारी को स्पष्ट करना चाहिए कि तथाकथित पाटित आयातों के कारण उत्पादन, बिक्री मात्रा तथा मूल्य, बढ़ावा लाभ, आदि में वृद्धि को देखते हुए क्षति हुई है। क्षति के समर्थन

में केवल एक यह स्पष्टीकरण दिया गया कि पूंजी निवेश पर आय अधिक नहीं हुई है। अगर ऐसा मामला होता तो अन्य कारकों का सही मूल्यांकन वास्तविक क्षति के निर्धारण से पहले प्रस्तुत कर दिया होता ।

(v) प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्ष में किसी और अन्य ज्ञात कारक को प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं:-

- (क) घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि ।
- (ख) व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धति जिससे अधिक ऊंची कीमत तय करने की कोशिश कर रहे घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन मिल सके ।
- (ग) घरेलू बाजार पर नए प्रवेशकर्ता का कीमत प्रभाव ।

30. मैसर्स टीएल वर्मा एंड कं० प्रा० लि० के विचार

(i) दो याचिकाकर्ता कंपनियों के लिए जिनके संबंध में प्राधिकारी ने क्षति का निर्धारण किया है, क्षति के निर्धारण में नियम 11 के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है ।

(ii) संबद्ध देशों से आयात काफी नहीं है- संबद्ध देशों से आयात का बाजार हिस्सा जांच अवधि के दौरान 1.67% रहा जबकि यह 2000-01 में 0.71% था । साथ ही, याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग का हिस्सा जो वर्ष 2000-01 में 38.37% था, बढ़कर जांच अवधि में 48.63% हो गया । इस प्रकार, संबद्ध आयात के हिस्से में 0.96% की वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग के हिस्से में 10.26% की वृद्धि हुई । आवेदन-पत्र में दिए गए आंकड़ों के अनुसार बाजार आकार जो वर्ष 2000-01 में 106 था बढ़कर जांच अवधि (9 महीने) 118 हो गया अथवा 158 वार्षिकीकृत । इस प्रकार, बाजार हिस्से में 52% से भी अधिक की वृद्धि हुई जबकि संबद्ध देशों से हुए आयात के हिस्से में मात्र 0.96% की वृद्धि हुई । संबद्ध देशों से किए गए आयात में वृद्धि को कभी भी अनुबंध के पैराग्राफ (ii) के प्रथम वाक्य के अर्थ के भीतर 'आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि' हुई कभी भी नहीं माना जा सकता । प्राधिकारी से अपेक्षा है कि वह बाजार के संदर्भ में हुई वृद्धि का मूल्यांकन करें ।

(iii) बिक्री मात्रा- घरेलू बाजार की बिक्री मात्रा में 17% से भी अधिक की वृद्धि हुई । इस आधार पर घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई ।

(iv) उत्पादन- उत्पादन के संबंध में क्षति का मूल्यांकन नहीं हुआ है ।

(v) क्षमता उपयोग- क्षमता उपयोग में मामूली वृद्धि हुई है। अतः इस आधार पर कोई क्षति नहीं हुई।

(vi) माल सूची- उत्पादन में गिरावट है और बिक्री मात्रा में 7% की वृद्धि हुई अतः माल सूची में वृद्धि नहीं हो सकी। ऐसा समझा जाता है कि निष्कर्ष में कुछ गलती है।

(vii) मजदूरी तथा रोजगार - ये कारक घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं दर्शाते।

(viii) लाभप्रदत्ता- प्राधिकारी से अपेक्षा है कि वह जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता की जांच करें और उसकी तुलना पिछली अवधियों से कर लें।

(ix) लगाई गई पूंजी पर आय- प्राधिकारी ने इस बात का कोई कारण नहीं दिया कि प्रतिशत कम क्यों रखा गया और लगाई गई पूंजी की आय का क्या प्रतिशत पर्याप्त समझा जाएगा।

(x) क्रम बिक्री कीमत- ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने फ्लोट ग्लास की सभी किस्मों के लिए एकल अहानिकर कीमत तथा जमीन पर उतारते समय के मूल्य का निर्धारण किया है। ऐसी एकल तुलना गलत है। अलग-अलग क्वालिटी/आकार की एनआईपी की तुलना आयात के लैंडिड मूल्य के अनुसार अलग-अलग होनी चाहिए।

(xi) कीमत कमी- कीमत कमी के लिए लैंडिड मूल्य की जांच घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के संदर्भ में की जानी चाहिए।

(xii) कीमत दबाव/मंदी - जहां तक कीमत दबाव/मंदी का संबंध है, प्राधिकारी के निष्कर्ष सही नहीं हैं क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उद्योग को जांच अवधि के दौरान अपेक्षतया ऊंची कीमत प्राप्त हुई। जब कीमतों में वृद्धि हुई है तो कीमत मंदी का प्रश्न नहीं होता।

(xiii) रोकड़ प्रवाह का वास्तविक एवं संभाव्य नकारात्मक प्रभाव- निष्कर्ष अत्यधिक व्यापक हैं। प्राधिकारी से अपेक्षा है कि वह जांच अवधि के दौरान वास्तविक रोकड़ प्रवाह का निर्धारण करे और उसकी तुलना पिछले वर्षों के रोकड़ प्रवाह से करें।

(xiv) वृद्धि- इस संबंध में किए गए निष्कर्ष अत्यधिक व्यापक हैं। प्राधिकारी इसका ठीक से मूल्यांकन करें।

(xv) चीन के संबंध में कोई क्षति नहीं - पाटन मार्जिन तथा कारखानागत निर्यात कीमत संबंधी सूचना से ऐसा प्रतीत होता है कि चीन से हुए आयात के लैंडिड मूल्य घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित एनआईपी की तुलना में अधिक हैं। अतः चीन से हुए निर्यात के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई।

(xvi) कारणात्मक संबंध - तथाकथित पाटित आयातों तथा तथाकथित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं हुआ है। कारणात्मक संबंध का निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने अन्य कारकों अर्थात् पाटित आयात से इतर कारकों का मूल्यांकन नहीं किया है जिनसे साथ-साथ घरेलू उद्योग को हानि हो रही है।

31. मै0 इम्पैक्ट सेफ्टी ग्लास वर्क्स प्रा0 लि0, बंगलौर के विचार

(i) देश में अत्यधिक पूंजी निवेश की वजह से, यदि कोई हो, भारतीय उत्पादकों को क्षति हुई है।

(ii) याचिकाकर्ता की ग्रुप कंपनियां मैसर्स ग्लेवरबेल और ग्लेवरमास दोनो असाही ग्रुप ऑफ कंपनी की इकाईयां हैं और याचिकाकर्ता स्वयं इस समूह की एक इकाई। मैसर्स ग्लेवरइंडिया भारत में एजेंट है। याचिकाकर्ता तथा मैसर्स ग्लेवरइंडिया रंगीन परावर्ती ग्लास का आयात करते हैं। इस कार्यकलाप से सम्पूर्ण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है क्योंकि इस मद का उत्पादन किसी भी फ्लोट ग्लास संयंत्र में अच्छी प्रकार हो सकता है। याचिकाकर्ता जांच अवधि के दौरान प्रभावकारी कीमत बढ़ाने में कामयाब रहे। रिकवरी तथा समृद्धि के चिन्ह हानि की बजाए जांच अवधि में स्पष्ट परिलक्षित हैं। स्पष्ट रूप से इन आयातों से घरेलू उद्योग पर कोई कीमत प्रभाव नहीं पड़ा।

(iii) घरेलू उत्पादन के अनुसार आयात मात्रा नगण्य है। कीमत का प्रभाव मात्रा के अनुसार होता है। किन्तु मौजूदा मामले में स्थिति उलट है। तथाकथित

कीमत प्रभाव का याचिकाकर्ता द्वारा अपनाए गए तरीकों की वजह से मात्रा कम करने का प्रभाव पड़ा ।

- (iv) घरेलू उद्योग के लाभ में पिछले वर्षों में वृद्धि होती रही । उनका लाभ जांच अवधि में विगत दो वर्षों की तुलना में सर्वाधिक रही ।
- (v) यह स्पष्ट नहीं कि क्या कम बिक्री कीमत के कारणों का संबंध आयातों से है।
- (vi) विगत दो वर्षों के दौरान माल की कीमतों में निरन्तर वृद्धि होती रही है । घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए इस वक्तव्य में कि उनपर अपनी कीमत कम करने का निरन्तर दबाव पड़ रहा है, वास्तव में सही नहीं है ।
- (vii) तथाकथित कीमत कम करने और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत कम करने के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है ।
- (viii) घरेलू उद्योग ने पहले इंडोनेशिया के इसी निर्यातक के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जिसमें यह आरोप लगाया गया कि इंडोनेशियाई निर्यातक प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धति पर चल रहे हैं । इस प्रकार याचिकाकर्ताओं ने उसके विरुद्ध वही कारण तथा प्रभाव के कारण बताए हैं । यह दावा करते हुए कि निर्यातकों द्वारा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है तो भारतीय उत्पादक अब इस बात का दावा कैसे कर सकते हैं कि उन्हें तथाकथित प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धति के कारण कोई हानि नहीं हुई है ।
- (ix) घरेलू उद्योग को वास्तविक हानि का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है ।
- (x) निर्दिष्ट प्राधिकारी को चाहिए कि वह पाटित आयातों से इतर अन्य ज्ञात कारकों की जांच करे जो घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारक हैं ।

32. घरेलू उद्योग के विचार

- (i) क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे पर प्रारंभिक निष्कर्षों में विचार कर लिया गया है और उनकी यहां पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है । अन्य इच्छुक

पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों के प्रत्युत्तर में घरेलू उद्योग ने निम्निलिखित निवेदन किए हैं ।

- (ii) आयातकों द्वारा दी गई दलील यह है कि संबद्ध देशों से किए गए आयात का हिस्सा जांच अवधि के दौरान 1.67% रहा जबकि यह वर्ष 2000-01 में 0.71% था । यह भी दलील दी गई कि घरेलू उद्योग के हिस्से में संबद्ध आयातों के हिस्से की तुलना में वृद्धि हुई है । निवेदन किया जाता है कि आयातों को पिछले वर्ष में प्राप्त हिस्से की तुलना में देखा जाए । ऐसी तुलना से यह इंगित होगा कि आयात के हिस्से में जांच अवधि के दौरान इससे ठीक पहले की अवधि की तुलना में दो गुनी वृद्धि हो गई । आयात की वृद्धि दर बाजार की वृद्धि दर की तुलना में अपेक्षतया अधिक है । आयात वृद्धि की नावा शावा पत्तन से हुए आयात को ध्यान में रखते हुए पुनर्मूल्यांकन किया जाए ।
- (iii) बिक्री मात्रा में हुई वृद्धि के संबंध में आयातक इस तथ्य को मानने में असफल रहे कि बिक्री मात्रा में वृद्धि की इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है कि देश में कुल क्षमता तथा उत्पादन दोनों में नए विनिर्माता के शामिल होने पर वृद्धि हुई । आयातक की यह दलील कि 17% की वृद्धि से क्षति हुई इंगित नहीं होती है, इसे इस कारक के गणितीय पहलू न कि आर्थिक मूल्यांकन के रूप में लिया जाए । निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे नई क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए बिक्री में हुई वृद्धि के मूल्यांकन करने पर विचार करें ।
- (iv) जहां तक घरेलू उद्योग के वास्तविक उत्पादन का संबंध है, प्राधिकारी इस तथ्य को स्वीकार करें कि उत्पादन में वृद्धि पूर्णतया नये विनिर्माता अर्थात् मै0 सेंट गोबेन की वजह से हुई है ।
- (v) लाभप्रदता तथा लगाई गई पूंजी के आय के संबंध में घरेलू उद्योग भारी पूंजी निवेश पर यथोचित आय-दर प्राप्त नहीं कर सका है , बावजूद इसके कि उनके पास विश्व-स्तर की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और उन्होंने एक निश्चित समयावधि में लागें कम करने हेतु व्यापक उपाय भी किए हैं । संबद्ध देशों से पाटित आयातों की वजह से घरेलू उद्योग को ऐसी आय प्राप्त नहीं हो पा रही है जिसे यथोचित समझा जा सके ।

- (vi) कीमत के कम-निर्धारण संबंधी प्राधिकारी के निष्कर्षों के संबंध में प्राधिकारी ने अपने निष्कर्षों में वास्तव में यह रिकार्ड किया है कि घरेलू उद्योग की आयातों के लैंडेड मूल्य के साथ औसत निबल बिक्री आय की तुलना यह तय करने हेतु की गई कि कीमत के कम निर्धारण की सीमा निश्चित की जा सके । कटौतीगत कीमत संबंधी उप-पैरा में दी गई सारणी में एनआईपी का संदर्भ अनभिप्रेत मुद्रण-त्रुटि है ।
- (vii) जहां तक चीन के लिए सामान्य मूल्य के कार्यचालन तथा अहानिकर कीमत के संबंध में आयातक की पूर्व धारणा का संबंध है, ऐसी दलील पूर्णतया दुराशी किस्म की है और इसकी कोई तथ्यपरक एवं कानूनी बाध्यता भी नहीं है । प्राधिकारी से आग्रह है कि वे अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर कार्रवाई करें ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

33. प्राधिकारी ने क्षति संबंधी विभिन्न दावों तथा प्रति दलीलों की निम्नानुसार जांच की:-

(i) संबद्ध देशों से आयात

संबद्ध देशों से कुल आयात वर्ष 1999-2000 में 10272 एम टी, 2000-01 में 2036.11 एम टी और जांच अवधि (9 महीनों) में 4406 एम टी अथवा 5874 एम टी (वार्षिकीकृत) का रहा । संबद्ध देशों से संबद्ध देशों से आयात में जांच अवधि(वार्षिकीकृत) के दौरान विगत वर्ष की तुलना में 188% की वृद्धि हुई । संबद्ध देशों से आयात में जांच अवधि के दौरान वर्ष 1999-2000 की तुलना में समग्र गिरावट आई । किन्तु, कुल आयातों में संबद्ध देशों से हुए आयातों के हिस्से जांच अवधि में बढ़कर 96.45% हो गए जबकि पिछले वर्ष में यह 20.87% और वर्ष 1999-2000 में 67.75% पर रहे थे । प्राधिकारी समझता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों में संपूर्ण रूप से वृद्धि हुई ।

(ii) बाजार हिस्सा:

संबद्ध माल की कुल मांग में संबद्ध देशों से होने वाले आयात जो वर्ष 2000-01 में 0.71% था बढ़कर जांच अवधि में 1.67% हो गया। संबद्ध माल की कुल मांग में याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जांच अवधि में गिरावट नहीं आई है। यह वर्ष 2000-01 में 38.37% पर रहा था जो जांच अवधि के दौरान बढ़कर 48.63% हो गया। किन्तु कुल मांग में अन्य देशों से होने वाले आयातों का बाजार हिस्सा जांच अवधि के दौरान घटकर 0.06% हो गया जबकि यह वर्ष 2000-01 में 2.71% था। संबद्ध माल की समग्र मांग में जांच अवधि के दौरान पिछले दो वर्षों की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के बाजार हिस्से में कुल मांग के बाजार हिस्से में हुई वृद्धि यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से वास्तविक रूप में तथा देश की मांग, दोनों दृष्टियों से वृद्धि हुई है।

(iii) घरेलू उद्योग का उत्पादन

प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन तथा क्षमता उपयोग निम्नानुसार रहा:-

वर्ष	क्षमता*	उत्पादन*	क्षमता उपयोग
1999-2000	100	100	76.48%
2000-01	151	156	79.09%
अप्रैल-दिस. 2001	167	171	78.43%
जांच अवधि वार्षिकीकृत	223	228	78.43%

* सूचीबद्ध आंकड़े

प्राधिकारी समझता है कि घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन में वृद्धि हुई है। किन्तु जांच-अवधि में हुई क्षमता वृद्धि के संदर्भ में क्षमता उपयोग में जांच-अवधि के दौरान विगत वर्ष की तुलना में 0.66% की मामूली गिरावट आई है।

(iv) बिक्री मात्रा:

घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा जो वर्ष 2000-01 में *** रही थी, बढ़कर जांच अवधि में *** हो गई। इससे वर्ष 2000-01 में लगभग 17% की वृद्धि परिलक्षित होती है। किन्तु बिक्री मात्रा में हुई यह वृद्धि घरेलू उद्योग की क्षमता में हुई वृद्धि के फलस्वरूप है। अतः बिक्री में हुई इस वृद्धि को निष्पादन में सुधार के लिए एकमात्र कारक नहीं ठहराया जा सकता।

(v) माल सूची

दिसंबर, 2001 में मार्च, 2001 को समाप्त पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग की माल सूची में 14% की वृद्धि हुई। जहां तक आयातक की इस दलील का संबंध है कि माल सूची में वृद्धि नहीं हो सकती जब तक बिक्री मूल्य में 17% की वृद्धि न होती और क्षमता उपयोग घटकर 0.66% रह गया, प्राधिकारी को लगता है कि घरेलू उद्योग की क्षमता जांच अवधि के दौरान 100 से बढ़कर 167(सूचीबद्ध) हो गई। उत्पादन भी 100 से बढ़कर 171 (सूचीबद्ध) हो गया। इसलिए, आयातक की मान्यता सही नहीं है। माल सूची में वृद्धि बढ़ी हुई क्षमता के फलस्वरूप अधिक उत्पादन मात्रा की तुलना में अपेक्षितया कम बिक्री के कारण हुई है।

(vi) रोजगार

घरेलू उद्योग में रोजगार स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(vii) मजदूरी

मौजूदा श्रम कानूनों के मद्देनजर उद्योग की मजदूरियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(viii) लाभप्रदता

प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग को जांच-अवधि के दौरान मामूली लाभ हुआ है।

(ix) बिक्रीगत कीमत

प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की अहानिकर कीमत की तुलना आयातों के लैंडिड मूल्य से की है और पाया कि पाटित आयातों के परिणामस्वरूप बिक्रीगत कीमत काफी ठीक है।

	चीन	इंडोनेशिया
एनआईपी	***	***
लैंडिड मूल्य	***	***
बिक्रीगत %	***(+ सका.)	***(+ सका.)

(x) कटौतीगत कीमत

कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को देखते हुए ऐसा जरूरी समझा जाता है कि इस बात की जांच की जाए कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में काफी हद तक कटौतीगत कीमत रही है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों में काफी हद तक मंदी आ जाएगी। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की औसत निबल बिक्री आय की तुलना आयातों के लैंडिड मूल्यों से की है और पाया कि कीमत में काफी कटौती की गई। आयातों से घरेलू बाजार की कीमतों पर अधिक दबाव/मंदी का रूख रहा क्योंकि घरेलू उद्योग में पाटित आयातों के मध्य नजर बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं हो सकी।

	चीन	इंडोनेशिया
औसत निबल बिक्री आय	***	***
लैंडिड मूल्य	***	***
कटौतीगत %	***(+ सका.)	***(+ सका.)

घरेलू उद्योग के लिए समान वस्तुओं की अहानिकर कीमत का निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने संबद्ध माल की वास्तविक उत्पादन लागत का प्रयोग किया जिससे घरेलू उद्योग के लिए अनुकूल उत्पादन लागत का निर्धारण हो सके जिसमें मानकीकृत सर्वोत्तम खपत मानदंडों तथा उस कच्चे माल की वास्तविक कीमत को शामिल किया जाएगा जिसकी खपत जांच अवधि के दौरान संबद्ध माल के उत्पादन में की गई थी। क्षति मार्जिन की गणना के प्रयोजनार्थ जांच अवधि के लिए

निर्धारित कारखानागत अहानिकर कीमत की तुलना आयातित माल के लैंडेड मूल्य से की गई है ।

क्षति के संबंध में निष्कर्ष

34. उपरोक्त के आधार पर घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले विभिन्न क्षतिकारकों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष दिए जाते हैं-

- i) संबद्ध देशों से संबद्ध माल के आयातों में पूर्ण रूप तथा देश में संबद्ध माल की मांग के संदर्भ में वृद्धि रही है ।
- ii) संबद्ध देशों से पाटित आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है ।
- iii) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में जांच अवधि के दौरान वर्ष 2000-01 की तुलना में वृद्धि हुई । किन्तु यह पाटित आयातों की वजह से अहानिकर कीमत (एनआईपी) से कम स्तर पर रही ।
- iv) उद्योग को पाटित आयातों द्वारा कटौतीगत कीमत के परिणामस्वरूप क्षति हुई है ।
- v) घरेलू उद्योग को कीमत दबाव के फलस्वरूप क्षति उठानी पड़ी । वे अपनी बिक्री कीमत को बढ़ा नहीं सके ताकि किए गए पूंजी निवेश पर उचित आय मिल सके क्योंकि पाटित आयातों के लैंडेड मूल्य के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में बहुत मंदी आई
- vi) घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है । ऐसा घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के फलस्वरूप हुआ है । बिक्री में यह वृद्धि मात्र निष्पदन में सुधार की वजह से नहीं हुई ।
- vii) दिसंबर, 2001 के अंत में मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष की तुलना में माल सूची में वृद्धि हुई है ।
- viii) घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

ix) उद्योग की मजदूरियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

x) प्राधिकारी निष्कर्ष देता है कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कटौतीगत कीमत तथा बिक्रीगत कीमत का होना है । संबद्ध देशों से संबद्ध माल के आयात के अपेक्षतया कम लैंडिड मूल्य के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को अपने उत्पादों के लिए उचित तथा यथोचित कीमत नहीं मिल सकी है । इसके फलस्वरूप पूंजी निवेश पर मामूली आय प्राप्त हुई । फ्लोट ग्लास उद्योग में पूंजी निवेश काफी भारी मात्रा में होता है और उद्योग द्वारा इस पूंजी निवेश पर प्राप्त कम आय से उद्योग को हानि हुई परिलक्षित होता है ।

xi) उपर्युक्त आर्थिक कारक संचयी तथा सामूहिक दोनों दृष्टियों से यह साबित करते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है ।

ड. कारणात्मक संबंध

35. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी ने पाटित आयातों के प्रभाव की जांच पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के सिद्धांत (v) के अनुसार किया है ।

प्राधिकारी का निर्णय है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण संबद्ध देशों से पाटित आयातों के परिणामस्वरूप कटौतीगत कीमत तथा बिक्रीगत कीमत रहे हैं । संबद्ध देशों से संबद्ध माल के आयातों के अपेक्षतया कम लैंडिड मूल्य के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग अपने उत्पादों के लिए उचित एवं यथोचित कीमत प्राप्त नहीं कर सका है । इसके परिणामस्वरूप पूंजी निवेश पर बहुत ही मामूली आय प्राप्त हुई है । फ्लोट ग्लास इंडस्ट्री में किए गए पूंजी निवेश काफी अधिक हैं और उद्योग द्वारा पूंजी निवेश पर प्राप्त कम आय के फलस्वरूप उद्योग को हुई हानि परिलक्षित होती है । संबद्ध माल की मांग में कमी नहीं आई है बल्कि इसकी बजाय उसमें वृद्धि हुई है और इसलिए मांग का कम होना क्षति का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है । प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि घरेलू उद्योग विश्वव्यापी स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा में है और घरेलू उत्पादकों में होने वाले प्रौद्योगिकीय परिवर्तन अथवा प्रतिस्पर्द्धा होने वाली हानि का कारण नहीं हो सकते । उद्योग में होने वाली किसी भी प्रौद्योगिकीय विकास अथवा ऐसा कोई कारक नहीं पाया गया जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो । 'उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह पाया गया है कि' अन्य

देशों से संबद्ध माल के आयात जांच-अवधि के दौरान डि-मिनिमस के कम स्तर पर रहे हैं। अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष देता है कि घरेलू उद्योग को जो क्षति हुई है उसका कारण संबद्ध देशों से संबद्ध माल के पाटित आयात हैं।

एआईएफजीएमए द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी, सीमाशुल्क तथा एमआरटीपी कमीशन के समक्ष पहले की गई शिकायतें

36. मैसर्स इम्पैक्ट सेफ्टी ग्लास वर्क्स प्रा० लि०, बंगलौर तथा अन्य आयातकों ने एआईएफजीएमए द्वारा इंडोनेशिया से होने वाले आयातों के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी, सीमाशुल्क प्राधिकारी तथा एमआरटीपी कमीशन के समक्ष पहले किए गए निवेदन के मुद्दे को पुनः उठाया। प्राधिकारी इस मामले में प्रारंभिक निष्कर्षों के पैरा 22-24 में की गई चर्चा को स्मरण करता है और अपने विचारों की पुष्टि करता है।

च. भारतीय उद्योग के हित

37. पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य सामान्यतः ऐसे पाटन को समाप्त करना है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच रही है और भारतीय बाजार में एक खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को बहाल करना है, जो देश के सामान्य हित में है।

38. प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तु के उपयोग से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामस्वरूप इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को लगाने से पाटन द्वारा प्राप्त किए गए अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग का ह्रास रुकेगा और इस प्रकार संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों को लागू करने से संबद्ध देश से होने वाले आयात किसी भी प्रकार कम नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

छ. निष्कर्ष

39. प्राधिकारी पूर्वोक्त पर विचार करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:-

(i) 2 एमएम से 12 एम एम तक की मोटाई (दोनों मोटाई शामिल) के स्पष्ट तथा रंगीन किस्म (हरे ग्लास को छोड़कर) फ्लोट ग्लास जिसमें परावर्ती ग्लास, सजावटी, औद्योगिक अथवा ऑटोमोटिव प्रयोजनों के लिए आशयित संशोधित ग्लास शामिल नहीं हैं, का संबद्ध देशों से उनके कम मूल्य पर भारत को निर्यात किया गया।

(ii) घरेलू उद्योग को वास्तविक हानि हुई है।

(iii) वास्तविक हानि संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा संचयी आधार पर हुई है।

40. ऐसा आवश्यक समझा जाता है कि संबद्ध माल के आयातों पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए। तदनुसार, प्राधिकारी 2 एमएम से 12 एम एम तक की मोटाई (दोनों मोटाई शामिल) के स्पष्ट तथा रंगीन किस्म (हरे ग्लास को छोड़कर) फ्लोट ग्लास जिसमें परावर्ती ग्लास, सजावटी, औद्योगिक अथवा ऑटोमोटिव प्रयोजनों के लिए आशयित संशोधित ग्लास शामिल नहीं हैं, के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

41. यह सिफारिश करने का निर्णय लिया जाता है कि पाटन मार्जिन के बराबर की राशि का पाटनरोधी शुल्क अथवा उससे कम, यदि लगाई जाए, के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त हो जाएगी आयातों की लैंडिड कीमत की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की अहानिकर कीमत से की गई। तदनुसार, ऐसा प्रस्ताव है कि 2 एमएम से 12 एम एम तक की मोटाई (दोनों मोटाई शामिल) के स्पष्ट तथा रंगीन किस्म (हरे ग्लास को छोड़कर) फ्लोट ग्लास जिसमें परावर्ती ग्लास, सजावटी, औद्योगिक अथवा ऑटोमोटिव प्रयोजनों के लिए आशयित संशोधित ग्लास शामिल नहीं हैं, जो संबद्ध देशों के मूल का हो अथवा वहां से निर्यातित हो और जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची के शीर्षक 70.05 के तहत क्लीयर किया गया हो, पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगा दिया जाए। पाटनरोधी शुल्क की राशि का उल्लेख नीचे दी गई सारणी के कॉलम 9 में अमरीकी डालर प्रति मी.टन में किया गया है-

क्र. सं.	उप-शीर्ष	माल का वर्णन	विनिर्देशन	उद्भव का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	70.05	फ्लोट ग्लास	2 एमएम से 12 एम एम तक की मोटाई (दोनों मोटाई शामिल) के स्पष्ट तथा रंगीन किस्म (हरे ग्लास को छोड़कर) फ्लोट ग्लास जिसमें परावर्ती ग्लास, सजावटी, औद्योगिक अथवा ऑटोमोटिव प्रयोजनों के लिए आशयित संशोधित ग्लास शामिल नहीं हैं,	चीन को छोड़कर कोई अन्य देश	इंडोनेशिया	कोई उत्पादक	पीटी मूलिया ग्लास	71.16	एमटी	अम.डा.
2	70.05	फ्लोट ग्लास	यथाउपयुक्त	चीन को छोड़कर कोई अन्य देश	इंडोनेशिया	कोई उत्पादक	पीटी टेंसिडो	77.76	एमटी	अम.डा.
3	70.05	फ्लोट ग्लास	यथाउपयुक्त	चीन को छोड़कर कोई अन्य देश	इंडोनेशिया	कोई उत्पादक	पीटी आब्दी राक्यात	81.21	एमटी	अम.डा.
4	70.05	फ्लोट ग्लास	यथाउपयुक्त	चीन को छोड़कर कोई अन्य देश	इंडोनेशिया	कोई उत्पादक	सभी निर्यातक-जिनमें पीटी मूलिया, पीटी टेंसिडो तथा पीटी आब्दी	81.21	एमटी	अम.डा.

							राक्यात शामिल न हो			
5	70.05	फ्लोट ग्लास	यथाउपर्युक्त	चीन	इंडोनेशिया	कोई उत्पा दक	कोई निर्यातक	81.21	एमटी	अम.डा.
6	70.05	फ्लोट ग्लास	यथाउपर्युक्त	कोई देश	चीन	कोई उत्पा दक	कोई निर्यातक	72.27	एमटी	अम.डा.

42. इस प्रयोजनार्थ आयात का लैंडिड मूल्य वह मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम 1962 तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 तथा 9क के तहत लगाए जाने वाले शुल्कों को छोड़कर सभी सीमाशुल्क के अनुसार किया जाएगा।

43. उपर्युक्त के अध्यक्षीन प्राधिकारी अपने दिनांक 20 नवम्बर, 2002 के प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करता है।

44. इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण में उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार दायर की जा सकती है।

एल. बी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2003

Final Findings

Subject : Anti-Dumping investigation concerning import of Float Glass originating in or exported from People's Republic of China and Indonesia.

No. 14/19/2002-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof.

A. PROCEDURE:

2. The procedure described below has been followed with regard to the investigations:-

i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received a written petition from All India Flat Glass Manufacturers' Association (AIFGMA), New Delhi on behalf of the domestic industry, alleging dumping of Float Glass (hereinafter referred to as subject goods) originating in and exported from People's Republic of China and Indonesia (hereinafter referred to as subject countries);

(ii) The following producers of Float Glass in India and members of the AIFGMA (hereinafter referred to as the petitioners) have specifically consented to participate in the anti-dumping investigations:

- (a) M/s. Saint Gobain Glass India Ltd., Kanchipuram, Tamil Nadu.
- (b) M/s. Float Glass India Ltd., Mumbai.

Another domestic producer, viz., M/s. Gujarat Guardian Ltd., Dist. Bharuch, Gujarat has supported the petition.

(iii) The Authority notified the Embassies of Peoples' Republic of China and Indonesia in India about the receipt of dumping application made by the petitioners before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra;

(iv) The Authority issued a Public Notice dated 5th July 2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti dumping proceedings concerning imports of Float Glass covered under Chapter heading/subheading 70.05 of Schedule I of the Customs Tariff Act;

(v) The Authority forwarded copy of the said public notice to the known exporters, importers and to the complainants and gave them an opportunity to make their views known in writing;

(vi) According to sub-rule (3) of Rule 6 supra, the Authority provided a copy of the petition to all the known exporters and Embassies of subject countries in India;

vii) Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of subject goods;

viii) The Authority provided copies of the non-confidential version of the Petition to the known exporters and the Embassies of the subject countries in accordance with Rule 6(3) supra;

ix) The Embassies of the subject countries were informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, petition and questionnaire sent to the exporters was also sent to them;

x) A questionnaire was sent to the known importers/users (as per details in the preliminary findings) of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4);

(xi) The Authority notified preliminary findings vide notification dated 20th November, 2002 and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;

(xii) The Authority also forwarded a copy of the preliminary findings to the Embassies of subject countries in India with a request that the exporters/producers of subject goods and other interested parties may be advised to furnish their views on the preliminary findings in the time frame as stipulated above;

(xiii) The Authority forwarded a copy of the preliminary findings to all the known exporters (whose details were made available by the Petitioner) other exporters who responded to the initiation notification, importers in India and they were requested to furnish their views, if any, on the preliminary findings within forty days from the date of the letter;

(xiv) The Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 19th February, 2003. All parties presenting views were requested to file written submissions of their views expressed. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any;

(xv) The Authority made available to all interested parties the public file containing non-confidential version of evidence submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7);

(xvi) Arguments made by the interested parties before announcing the preliminary findings, which have been brought out in the preliminary findings notified have not been repeated herein for sake of brevity. However, the arguments raised by the interested parties subsequently have been appropriately dealt in the disclosure statement and these findings;

(xvii) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties on 25th June, 2003 vide a disclosure statement and comments received on the same have also been duly considered in these findings;

(xviii) Cost investigations including spot verification (as deemed necessary) of the domestic industry were also conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the Petitioner.

(xix) The Authority conducted on the spot verification of information furnished by the exporter M/s PT Mulia Glass, Indonesia.

(xx) *** in this notification represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules;

(xxi) The investigation covered the period from 1st April, 2001 to 31st December, 2001.

(xxii) Copies of the Initiation Notice and Preliminary Findings were also sent to FICCI, CII, ASSOCHAM etc. for wider circulation.

B. VIEWS OF PETITIONERS, EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES AND EXAMINATION BY AUTHORITY.

3. The views expressed by various interested parties have been discussed in the preliminary findings and also in the disclosure statement. The views which have not been discussed earlier in the preliminary findings and disclosure statement and those now raised in response to the disclosure statement are discussed in the relevant paragraphs herein below to the extent these are relevant as per rules and have a bearing upon the case. The arguments raised by the interested parties have been examined, considered and, wherever appropriate, dealt in the relevant paragraphs herein below.

4. At the Preliminary Findings stage responses had been received from the following:

Exporters: -

- (i) PT Mulia Glass, Indonesia.
- (ii) PT Abdi Rakyat Bakti, Indonesia.
- (iii) PT Tensindo, Indonesia.
- (iv) M/s Qinhuangdao Huazhou Glass Co. Ltd., China
- (v) M/s Nanning Float Glass Co. Ltd., China

Importers

- (i) M/s. Monika Exim International Ltd., Pune.
- (ii) M/s. Liberty Glass House, Mumbai.
- (iii) M/s. Impact Safety Glass Works Pvt. Ltd., Bangalore
- (iv) M/s. Mahaveer Mirror Industries
- (v) M/s. T.L.Verma & company (P) Ltd.
- (vi) M/s Samarth Industries, Mumbai
- (vii) M/s Rajvi Enterprise, Mumbai
- (viii) M/s Chinoy Chablani & Company, Calcutta

The submissions made by various interested parties had been dealt with in the preliminary findings and these are not being repeated here for the sake of brevity.

Views expressed by M/s Monika Exim International Ltd., Pune and M/s Navakar Impex Pvt. Ltd., Chennai in response to Disclosures :

5. It has been argued that the Disclosures issued by the Authority are deficient as under:

Initiation : The application for initiation was without a letter from the petitioners and supporters.

Procedure : Many of the interested parties were not sent the copy of initiation notification dated 5.7.2002 and their names were not disclosed in the list. Even the foreign exporters like PT Tensindo and PT Abdi Rakyat Bakti were not sent the copy of the preliminary findings and were not informed about the public hearing held on 19.2.2003.

Non-Disclosure of Civil Appeal : The fact of pending court cases / interim orders of Hon'ble High Court have not been mentioned in the Disclosures.

Period of Investigation : It was essential to segregate the reflective glass imports from Float Glass before initiating the investigation. Initiation was done in July, 2002, i.e. seven months after the last date of POI.

Product under Consideration and Like Article : It is not disclosed as to why production quantity of item sheet glass is not considered as Like Article. If production of sheet glass is considered, the petitioners would not fall under the definition of domestic industry.

Margin of Dumping :

- (a) The Designated Authority has not disclosed the reasoning for taking the Normal Value as constructed cost of manufacturing for domestic petitioners instead of the Normal Value of PT Mulia in the case of the Chinese manufacturers. The Authority should consider the Normal Value as that of PT Mulia instead of highly inflated cost of manufacture of the domestic petitioners.
- (b) In the absence of response from Chinese manufacturer, the Authority has not disclosed how the proof of export price from China has been calculated to achieve the dumping margin.
- (c) The Authority has failed to disclose its reasoning for calculating the Normal Value, export price and margin of dumping on weighted average basis.
- (d) The Normal Value provided by PT Mulia has been upheld for other Indonesian suppliers. The export price for the three manufacturers is alike specially for the 4mm and 5mm clear float glass. The Designated Authority has not disclosed the flawed calculations. As the Normal Value and export price are same for the three manufacturers, how dumping margin of PT Tensindo and PT Abdi can be higher when compared with PT Mulia.

Assessment of Injury :

- **Imports from subject countries:** The annualized import figures, which have not been disclosed, have been used to suggest the increase in volume of imports from the subject countries when actual figures should have been available. Actual or even annualized import data relied upon has not been disclosed. There has been drastic reduction in the total quantity of imports when compared to the year 99-2000. During the year 99-2000, the imports have said to be 10272 tones whereas during the POI it has fallen to 4406 MT and annualized to 5874.67 MT.

It can also be seen from the table 4.1 of the application that the import from the subject countries in comparison to the demand in the country, imports gave drastically reduced from 9.15% in 99-2000 to 1.71 in 2000-01 and 3.32 % during the POI though there have been drastic increase in the total demand of the country from 100 to 118.18

- **Market share:** The petitioners appear to have presented only annualized figures of sales volume of subject goods during POI when actual figures were available at the time of submitting the application. The annualized sales volume figures relied upon by the Designated Authority have not been disclosed.

It has not been disclosed as to how the demand for the subject goods in relation to the demand in the country has increased. As a matter of fact it has been disclosed that the said demand in comparison the domestic industry has decreased.

The market demand data for subject goods, which is by nature non-confidential, has not been disclosed. The Designated Authority in evaluation injury parameters has used this data.

- **Production of Domestic Industry:** The installed capacity of the petitioners for the subject goods has not been disclosed. The information regarding installed capacity is significant to evaluate and examine level of investments and operations and return on capital claimed and adopted by domestic industry.

Optimum and not any actual level of capacity utilization in terms and actual figures for the domestic industry has not been disclosed.

The DA has noted that there has been an increase in capacity of production and due to the increase only a marginal decrease of 0.66% in capacity utilization has occurred. The DA has failed to show how an injury can be claimed on this. As a matter of fact the DA has not disclosed a better performance on account.

The DA has also not disclosed that the supporting company M/S Gujarat Guardian has been running at almost 110% capacity during the POI.

The market share of the domestic industry has been consecutively increasing and when it is clearly accepted by the domestic industry that there has been increase in the market share there is no reason that imports would cause any injury and therefore, no injury is caused or proved due to the imports. The capacity utilization near to 80% is generally treated as optimum worldwide and fall of meager percentage of 0.66 in the capacity utilization may be due to the increase in the new capacities.

- Sales Volume: The alleged normative basis of working out fair selling price has not been disclosed. It is not shown as to how injury to the domestic industry on account of some unexplained "other factors" is nullified. What are these "other factors" has also not been disclosed.

It is pertinent to note that how the ADA is satisfied to accept the contention of the domestic industry that the increase in the market share of the domestic industry has to be viewed in the context of the addition of the new capacity in the country, if such is the case, that market share increases with the set up of new capacities, why should there be fear of imports because the addition of import is like addition of new capacity as the market is big enough to consume the increased capacities.

- Inventory: The DA has not disclosed the reasoning for comparing inventory levels with that of at the end of December, 2001 in comparison to the previous year closing on March, 2001. The inventory levels can only be compared with year end to year end or December 2001 to December 2000 to come to a correct level of comparison.
- Employment: The DA has not disclosed that there is no Injury on these grounds.
- Wages: The DA has not disclosed that there is no Injury on these grounds.
- Profitability: The DA has not disclosed that the Profits made by the domestic industry have been the highest during the POI when compared to the previous entire history of the domestic industry. Also, not disclosed is that the company m/s Saint Gobain, petitioner, is a new company and has shown much better results when compared with their projections in their project reports. Also not disclosed is that the supporter Gujarat Guardian Ltd, Has made a profit of around Rs. 50 Crores during the POI.

- **Price under selling:** Optimum and not any actual cost of production for producing subject goods have not been disclosed. It has not been shown as to how fair selling price or non-injurious price, which is stated, to be due to the domestic industry has been worked out and what are the costs involved therein and the underlying assumptions. The difference between the fair selling or non injurious price whose method of computation, cost involved, basis and assumptions have not been disclosed and the landed value of the imports is in fact the actual imposition of provisional anti dumping duty and therefore the entire basis and working of arriving at the fair selling or non injurious price was required to be disclosed.
- **Price under cutting:** The DA has not disclosed that the domestic industry increased the selling price of their product during the POI by at least 65% when compared to the previous AY. In the presence of the above how can any price underselling or injury due to this be claimed? If price undercutting was there, then increase in selling price would not have been possible. The ADA has not disclosed "other factors" that are said to have resulted in the sale price improvement of the domestic industry and the extent to which the sale price increase was accounted for by increase in raw material price.
- **Returns on Investment:** The DA has not disclosed that in view of the increased capacity in the preceding year a fair ROI was not possible for any of the manufacturers, in spite this all have shown a better ROI during the POI. The authority has not disclosed what a fair ROI is expected by the petitioners. The supporting company has earned a profit after tax and depreciation of over 10% of their investments during POI. The fair and not any actual return on investments to which the domestic industry is stated to be entitled to has not been disclosed by the ADA in the disclosure statement. What is the fair level of investment on which fair returns have been calculated and assumed has not been disclosed.

The analysis of financial information if provided by the domestic industry and the results of verification done by the authority to examine the impact of imports on domestic industry's Return on Capital employed has not been disclosed.

What is the methodology adopted in this analysis has not been shown or explained. The price-undercutting table does not disclose any figure, which should have been disclosed to arrive at the exact price undercutting if any. The price undercutting was not due to the imports but due to the competition among the domestic manufacturers wherein the float glass industry has planned to wipe out the sheet glass industry in phased manner.

- Actual and Potential negative effects on cash flow: There is no analysis disclosed or discussed of the designated authority on the aspect that negative cash flow of the petitioners was a function of several other factors, which too have not been disclosed.
- Growth: The DA has not disclosed of the additional investments made by the supporting company.
- Causal Link:

It has been time and again been brought to the notice of the DA, that not only must the DA study, the alleged dumping, it must also study the effect of dumping to the domestic industry and any injury thereof. And also the DA must verify that the injury being caused to the domestic industry is by the effects of dumping only and that there is a clear causal link between the two. And if any other factors are causing the injury, this must not be attributed to dumping.

In the present case, there is no injury to the domestic industry on account of alleged dumping. This is very much clear from the balance sheets of all, the petitioners as well as the supporters. If any injury were observed, the balance sheets would have shown a negative performance rather than a positive when compared with the immediate preceding three years as is in the case of the present investigation. The DA has not disclosed this.

The rules clearly specify, if any restrictive trade practices between domestic and local producers exist, the injury caused by this must not be attributed to dumping. The DA has time again pointed out to the ruling of the Supreme Court, which has only shown that the both the MRTPC and the ADD have separate jurisdictions to cover this matter. The case at the MRTPC is still pending on account of injury being caused to the domestic producers on account of Restrictive trade practice. If injury by supply of low priced goods due to the petitioners at the MRTP are claiming a restrictive trade practice. Then as the ADD rules specify, no injury caused due to this factor may be attributed to dumping. In other words, the ADD must segregate the quantum of injury due to the Restrictive trade practice and must not attribute that amount to Injury being caused due to dumping, if any.

- The exact causal link in terms of the price, value and the volume of the imports and that of the domestic industry is not established or disclosed.

6. Authority's views

- a) The Authority is of the view that the Disclosures issued on 25th June, 2003, under Rule 16 of the Anti Dumping Rules contained the essential facts

under consideration of the Authority which would form the basis for its final findings. The submissions made by various interested parties at the stage of preliminary findings had been addressed and dealt with at the time of issue of preliminary findings notification dated 20.11.2002. The Disclosure Statement as per Rule 16 are required to contain the essential facts under consideration of the Authority which form the basis for making final determination. It is not permitted to bring in new issues at this stage by any interested party as sufficient time had already been given to the interested parties to offer comments after initiation of investigation, after issue of preliminary findings and after holding of the public hearing.

b) As regards arguments on initiation that the application for the initiation was without a letter from the petitioners and supporters, the petition contained the letter of All India Flat Glass Manufacturer Association. Upon request made by the importer M/s Monika Exim International Ltd., a copy of the said letter dated 26th April, 2002 was supplied to them by the Designated Authority vide letter dated 1st October, 2002.

c) As regards points raised regarding procedure of forwarding of initiation notification and preliminary findings to various interested parties, the Initiation Notification dated 5.7.2002 and the Preliminary Findings dated 20.11.2002 were sent to all the known interested parties, Embassies of the subject countries in India and to those exporters / importers who had participated in the investigation. In this regard, para 2 of the preliminary findings notification also refers. The Authority also received acknowledgment about receipt of preliminary findings notification dated 20.11.2002 from exporters M/s PT Tensindo. As regards Public Hearing held on 19.2.2003, notice of same had been issued on 22nd January, 2003 and all interested parties had been informed. Exporter, M/s PT Mulia confirmed by their e-mail dated 17.2.03 about receipt of the notice of the public hearing and informed that they would not participate in the public hearing. M/s Mahavir Mirror Industries, Chennai, M/s Navakar Impex Pvt. Ltd., Chennai acknowledged the receipt of the notice of public hearing but did not attend the same on the plea that they had challenged the preliminary findings before the Hon'ble High Court, Madras and that in view of the interim orders of the Court, all further decisions including the final findings were to be kept in abeyance. M/s Monika Exim International Ltd. neither responded to the notice of public hearing nor did they attend the public hearing. The representative from the Ministry of Industry, Republic of Indonesia and officials of the Embassy of Indonesia in India attended the public hearing, among others. The Authority is of the view that the procedure as laid down under Anti Dumping Rule 6 was duly followed and the interested parties were given opportunity to make oral submissions in the public hearing held on 19.2.2003. The parties attending the public hearing made written submissions thereafter which were also exchanged. The parties thereafter made rejoinders on the submissions of other parties. Some of the importers and exporters did not attend the public hearing for the reasons best known to them, however they can not claim that opportunity of oral hearing was

not given to them. Rather the opportunity given to them was not availed by them. There were no directions from the Hon'ble High Court to restrain the Designated Authority from proceeding further in the investigation. Therefore, the Authority does not find any merit in the arguments of the importers as regards not following the procedure in the conduct of the investigation.

d) As regards arguments raised on other issues viz. POI, Product under consideration and Like Article, dumping margin, injury assessment, the same have been dealt with at appropriate places in these findings.

7. Writ Petitions / Appeals before the Hon'ble High Court

- a) Some of the importers of Float glass had filed writ petitions / appeals before the Hon'ble High Court of Madras challenging the validity of the Preliminary findings Notification dated 20.11.2002. In the WP Misc Petition 1812/2003 in WP 1451 of 2003 of M/s Mahavir Mirror Industries and WP Misc Petition 3985/2003 in WP 3193 of 2003 of M/s Monika Exim International Ltd. and WP 1810/2003 in WP 1449 of 2003 of M/s Navakar Impex Pvt. Ltd., the Hon'ble High Court had issued interim orders on 20.1.2003 and 3.2.2003 stating that there will be an interim stay to the effect that the Central Government to proceed only up to the stage of Rule 13 and further decision shall be kept in abeyance until further orders. Thereafter, the WP 44506 & 44507 of 2002 of Mahavir Mirror Industries and WP 3193 & 3194 of 2003 of Monika Exim had been dismissed by an order dated 13.3.2003 of Hon'ble High Court of Madras. The said importers had challenged, inter-alia, the legality of the Preliminary Findings dated 20.11.2002 and the validity of Rule 7 relating to confidentiality information, non-compliance of principles of natural justice in the shape of personal hearing prior to the issue of preliminary findings. The Hon'ble High Court did not find any justification in the Writ Petitions of these importers and therefore, dismissed the same.
- b) Subsequently, in the WA Misc Petition 2091 and 2092/2003 of M/s Mahavir Mirror Industries and WA Misc Petition 2093 and 2094/2003 of M/s Monika Exim International Ltd., the Hon'ble High Court, Madras passed following orders on 16th April, 2003:

Having heard either counsel in all these matters and having regard to the facts and circumstances of the case and balance of convenience, we direct, that in all these cases, the goods be released on furnishing bank guarantee towards Anti-Dumping Duty. We make it clear that in the event of writ appeals being allowed, the bank guarantee shall be revoked or otherwise on the failure of the payment of Anti-Dumping Duty, the bank guarantee will have to be invoked.

From the above orders of the Hon'ble Court, it is evident that there are no directions to the Designated Authority to stop proceeding further in the investigation.

8. Product under Consideration and Like Article :

The product under consideration in this investigation is 'Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes'.

Subsequent to the Preliminary Findings, following views / comments have been received :

Views of All India Flat Glass Manufacturers' Association (AIFGMA) :

(i) The description of the product under consideration is specific and covers only clear and tinted glass. Accordingly, the above product definition cannot include 'reflective glass' which are processed and do not remain clear and tinted so as to come under the scope of the anti dumping investigation. The Association had no intention of getting anti dumping duty levied on 'reflective glass' imported from China and Indonesia as the same do not injure the domestic industry and is a processed glass which is imported at substantially higher prices than Float Glass. It is, therefore, requested for exclusion of reflective glass from the notification imposing anti dumping duty on Float Glass.

(ii) It is abundantly clear that sizes below 2mm and above 12mm are not proposed to be covered within the purview of the investigation nor do the reflective glasses form part of the investigation. In the chart submitted by the importer they have indicated that the Domestic Industry does not manufacture some non-standard thickness like 3.2 mm, 4.2mm, 5.5mm etc. In this connection, it is respectfully submitted that normally glass is sold in standard thickness only and glasses of non standard thickness are perfectly substitute to the Domestic Industry's range of products, both technically and commercially. Thus, the importer has not been able to point out any product which is not like article to the Product Under Consideration or the product range of the Domestic Industry. This is without prejudice to the fact that the contention of the importer about the non-production of certain thickness is also incorrect.

Views of Impact Safety Glass Works Pvt. Ltd. Bangalore :

There are other manufacturers of Flat Glass in India who are part of the Association and who produce similar or substitutable items. The petitioner has not admitted these companies as Indian producers. In case the product being produced by these companies is not a like product, the relevant issue would be whether the product being imported from Indonesia and China is a like product.

The Indian producers must be in production of 'like article'. For the goods imported from the subject countries, the goods produced by all these producers who have not been acknowledged as Indian Producers are like articles. These producers could not have been, therefore, ignored by the petitioners, more so when these companies are members of the Association.

M/s Monika Exim International Ltd. and M/s Navakar Impex Pvt. Ltd. have raised an issue in response to the Disclosure Statement that it has not been disclosed why Sheet glass has not been considered as Like Article.

Examination by the Authority :

The Authority recalls the Preliminary Findings wherein under para 19, the issue of domestic industry has been dealt with. The Authority has observed that M/s Haryana Sheet Glass Ltd., M/s Gujarat Borosil Ltd. and M/s IAG Company Ltd. are manufacturers of Sheet Glass. The other producer M/s Triveni Glass Ltd., who manufactures Float Glass, has already been shown as manufacturer under 'other producers' in the petition. The Authority is of the view that the present investigation relates to 'Float Glass' and the arguments made by importers M/s Monika Exim and M/s Navakar Impex Pvt. Ltd. to include sheet glass within the scope of the product under consideration and Like Article is irrelevant and devoid of justification. The Authority confirms the Preliminary Findings as regards the Product under Consideration subject to the clarification given by the domestic industry to exclude reflective glass from the scope of the investigation and imposition of anti dumping duty. The authority notes that the subject goods being imported from the subject countries technically and commercially substitute the domestic producers' product. It may be that Float Glass of some thickness may not have been produced by the domestic industry during the period of investigation. Yet the domestic industry is capable of producing the same and the imported subject goods are commercial substitute of the domestically produced Float Glass. The imported subject goods have characteristics closely resembling those of the domestic product. In the absence of any other significant arguments on the issue of Like Article, the Authority confirms its views that the Product under Consideration being imported from the subject countries is a Like Article to the Float Glass being produced by the domestic industry.

9. Period of investigation :

The period of investigation in the present investigation is from 1st April, 2001 to 31st December, 2001. It has been argued by the importers viz. M/s Monika Exim International Ltd., Pune and M/s Navakar Impex Pvt. Ltd., that the import data of secondary sources also included reflective glass which is not a part of the item under investigation. The item reflective glass is also falling under HS Code 70.05 and it was essential to segregate the reflective glass from clear and tinted float glass before initiating the investigation. The reason for not segregating reflective glass from the item under investigation is not disclosed. Further, it has

been argued that data is provided by Customs Houses officially on payment of fees and therefore, depending on secondary source data gives grounds for suspicion. The initiation was done in the month of July, 2002 i.e. seven months after the last date of POI. It is not digestible to say that data were not available from reliable sources even after seven months. Further it has been argued that how quarter-wise information in respect of POI was helpful to the Authority in making appropriate analysis when information pertaining to POI of nine months is compared with two full accounting years. The Authority is of the view that the anti dumping agreement does not lay down the period of investigation. However, it should not be less than six months. The Authority also notes that the importers have raised the above arguments at a very belated stage i.e. after the issue of Disclosures. The importers or any interested party were fully aware of the period of investigation and the data relied upon by the petitioners. Nonetheless the authority has examined this aspect. The Authority has referred to the petition of the domestic industry wherein a 'Note on Collation of Import Data' had been annexed. It had been clearly stated in the said Note by the petitioner that the statistics published by the DGCI&S give combined details of all types of Float Glass and surface ground or polished glass imports into India from various countries. However, the petition related to *'Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes'* which were being dumped and causing injury to the domestic industry. The Note further stated that the petition sought to cover only subject Float Glass for which no dedicated heading exists nor is the data compiled by any agency (including DGCI&S) in that manner. The petitioner also stated that in view of the fact that DGCI&S data was not available for the subject goods, they had collected and collated the same from Impex Data Services and the data available for ICD, Delhi from BE Register. The Authority does not find substance in the argument of the importers about inclusion of reflective glass in the volume of imports of subject goods as claimed in the petition by the petitioner. Moreover, the volume of imports of subject Float Glass is also corroborated from the response of the exporters. Therefore, the Authority considers that the period of investigation in this case is appropriate.

10. Domestic Industry

Views of M/s T.L. Verma & Co. Pvt. Ltd.

- (i) Two petitioner companies do not represent a major proportion of the total output of the domestic industry in India and therefore, the investigation is liable to be terminated. There are two more producers in India, viz. (1) Gujarat Guardian Ltd. and (2) M/s Triveni Glass Ltd. Out of the two producers, M/s Gujarat Guardian Ltd. has supported the petition. M/s Triveni Glass Ltd. has not supported the petition.

- (ii) The petitioners represent 49.49% of the total production of the subject goods in India during the period of investigation. The petitioners along with the supporting manufacturer constitute 82.09% of total domestic production of the subject goods in India.
- (iii) Only the two petitioner companies have furnished detailed information regarding the status of the domestic industry to the Authority. The supporting company has not furnished the relevant details to the Authority.
- (iv) In terms of Rule 11(2) read with Rule 2(b), the injury should be established for the domestic industry which should cover at least those domestic producers whose collective output of the subject goods constitute a major proportion of the total domestic production of that article in India. In this case, the total production of the two petitioner companies alone does not constitute a major proportion of the total domestic production in India. Thus the petitioner companies cannot be treated as domestic industry within the meaning of Rule 2(b).
- (v) The deeming provision regarding 25% standing contained in proviso to Rule 5(3)(a) is not applicable here. The phrase 'domestic industry' appearing in Rule 11 as also in the Annexure-II shall be interpreted in accordance with the definition given in Rule 2(b). Since Rule 2(b) specifies the major proportion requirement, it is necessary that injury determined for the two domestic producers will fulfill Rule 11(2) only if they pass the major proportion test. In this case, the two domestic producers have failed to pass the major proportion test. The injury determination is, therefore, flawed and the provisional duty is illegal and deserves to be withdrawn.
- (vi) Therefore, the domestic industry should cover three companies in this case i.e. two petitioner companies M/s Saint Gobain Glass Ltd., M/s Float Glass India Ltd. and the supporting company M/s Gujarat Guardian Ltd. Considering data in respect of two petitioner companies alone will not amount to considering the situation of the domestic industry.
- (vii) As the domestic industry has failed to produce sufficient evidence of injury to the domestic industry, the investigation may be terminated under Rule 14(b).

Views of Petitioner

- (i) In the case of Hexamine, this issue had been argued before the Authority but was over ruled and the Designated Authority considered that injury analysis for the Domestic Industry can be done even if the

petitioner Domestic Industry accounts for less than 50% of the country's production. In this case, through out the injury analysis, only the information relating to the two petitioners had been considered. The exception has been made only while analyzing the sales and market share for the petitioners when the sales data of other producers had also been considered.

- (ii) In the instant case also, the Designated Authority has considered the information of the entire domestic industry and not of the petitioner alone while analyzing the factors relating to market share. The analysis in the case of Float Glass is in line with the approach taken by the Designated Authority in the previous cases.
- (iii) The representative of the importer has not submitted any authority to support their case as to why the term 'major proportion' should necessarily imply those who account for more than 50% of the domestic production.
- (iv) Without prejudice to the above, while filling the application, the responsibility of the domestic industry is to present the information with regard to the petitioner as well as other producers for the purpose of 'standing' to file the petition. At this stage, the information with regard to the other producers is collected by the petitioners from the best available sources. We have now collected the certified information from the non-petitioner domestic producers which indicate the petitioners themselves account for more than 50% of the production as per table given below:

Petitioners	PERIOD OF INVESTIGATION	
	Qty (MT)	Rs.(Lakhs)
Floatglass India Ltd.	96122	15541
Saint-Gobain Glass India Ltd.	95641	15743
Total for Petitioners	191763	31284
Supporting Producers		
Gujarat Guardian Ltd.	107441	19456
Total for Supporting Producers	107441	19456
Other Producers		
Triveni Glass Ltd.	51060	7713
Grand Total	350264	58453

% of Petitioners	54.75%	
% of Petitioners & Supporters	85.42%	

- v) It may be seen from the above that the petitioners themselves account for 54.75% of the total domestic production of the like articles.

M/s T.L. Verma & Co. Pvt. Ltd. have given following views in their rejoinder and on the Disclosures :

- (i) The petitioner companies should have established their status as 'domestic industry' at the time of making the application. According to the data submitted by them, collective output of the two petitioner companies was less than 50%. This is evident from the preliminary findings. All of a sudden, in the written submissions, the petitioner gives some new data stating that the production of non-petitioner companies are less and therefore, share of the petitioner companies is more than 50% of the total domestic output. There is no basis for such a claim. This claim is not based on facts. Even the revised data does not give 'actual output' but only annualized output.
- (ii) The petitioner had an obligation to submit correct details at the time of filing the petition so as to establish beyond reasonable doubt that they fulfill the standing criteria.
- (iii) The action of the Authority in the Hexamine case was legally not sustainable. In terms of Rule 11(2), the Authority is required to evaluate injury for the domestic industry. In terms of Rule 2(b), the domestic industry means, the domestic producer as a whole or those producers whose collective output represent a major proportion of the total domestic output. Therefore, legally, the Authority is bound to evaluate injury for such of those domestic producers, whose collective output passed the major proportion test.
- (iv) The Authority has accepted the production volume of non-petition companies without any verification. There is no mention about why and on what basis, the figures were amended at the late stage in the proceedings. In terms of Rule 8, the Authority is required to satisfy itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties upon which the findings are based.

Comments of M/s Monika Exim International Ltd. and M/s Navakar Impex Pvt. Ltd.

The product of the petitioners, Triveni float glass, Indian sheet and imported glass should be treated as Like Article, if the petitioners treat the imported glass as Like Article with the petitioner's float glass. If the Designated Authority takes this position, the petitioners would not fall under the definition of domestic industry as they would not represent the major proportion of the Indian total production. Even now the petitioners are below the major proportion. In the Disclosure Statement, the Authority has changed the earlier stand taken in the preliminary findings by stating that the petitioners account for 54.75% instead of 49.49% as stated earlier. The Authority is required to disclose the data they relied on at the time of initiation of investigation.

Examination by the Authority

The Authority has examined the various arguments on the issue of domestic industry. The petitioners have also furnished letters from the other two domestic producers viz. M/s Gujarat Guardian Ltd. and M/s Triveni Glass Ltd. The two companies have confirmed their production of subject goods during the period April-December, 2001 as under :

M/s Gujarat Guardian Ltd.	107441 MT
M/s Triveni Glas Ltd.	51060 MT

The Authority has also checked that the above production figures are for the period April-December, 2001 and not annualized as incorrectly mentioned by the petitioners in their letter dated 3.3.2003 subsequent to the Public Hearing. The total production of subject goods by the four producers during POI April-December, 2001 is 350264 MT. Out of this, the share of the two petitioner companies viz. M/s Float Glass India Ltd. and M/s Saint Gobain Glass India Ltd. is 191763 MT. This comes to 54.75% of the total production. The Authority is of the view that the aforesaid two non-petitioner companies have confirmed in writing about their production of subject goods during the POI. The Authority considers the same as correct. In any case, the petition enjoyed the support of producers of subject goods that represented more than 50% of the domestic production even at the stage of initiation. As the share of the two petitioner companies viz. M/s Float Glass India Ltd. and M/s Saint Gobain Glass India Ltd. is 54.75% of total production, they represent the major proportion of the total domestic production of subject goods. The Authority considers the two petitioner companies to represent the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and Rule 11(2). For the purpose of evaluation of factors viz. total demand of the subject goods and net sales realization, the Authority has considered the information relating to the supporting producer M/s Gujarat Guardian Ltd. also.

11. Submission of Non-confidential Information

Views of M/s T.L. Verma & Co. Pvt. Ltd.

The note on collation of import data referred to in the findings was silent as to the method followed in converting quantity from Sq. Mtr. to MT in the absence of thickness. The import data published by IMPEX statistics services did not contain 'thickness' details in all the transactions. This is a crucial element in determining the volume of imports. Therefore, the opposing interested parties have a right to know how the data conversion took place. We had also asked them to disclose the factor used in converting the Sq. Mtr. into MT and the basis therefor. Further, the non-confidential version of the petition is completely blank in respect of Proforma IVA (except item 1 relating to import data), table on profitability, sales volume, cost of sales, unit price and loss or profit, return on investment, price under selling, price under cutting and Proforma IVB.

The Authority has not disclosed the basis and methodology followed in determining NIP and injury margin for the domestic industry.

Views of Government of Indonesia

Level of confidentiality used in the notification is unjustified in the light of requirements of Article 6.5 of the Agreement. The price effect of the dumped imports is clearly of importance in that price undercutting is alleged resulting in price suppression. However, no adequate non-confidential summary of the basic price information is presented. At least, the information should be provided in indices and %terms to substantiate the examination undertaken by the Investigating Authority.

Views of Petitioners

- (i) We are concerned about the facts that the Designated Authority has accepted the information submitted by PT Mulia Glass despite the fact that they have not supplied the non-confidential version of their response thereby failing to fulfill their legal obligation. Para 5(i) of the Preliminary Findings refers in this regard.
- (ii) The parties raising objection about the inadequacy of non-confidential version submitted by us, in their own submission have not given any information. All the seven annexures to the importer's questionnaire submitted by them are either blank or contained an assertion that 'information not susceptible for summarization as the information is highly sensitive'.

Examination by the Authority

- (i) As regards submission of non-confidential version by exporter, M/s PT Mulia Glass, the same had been furnished by the exporter and copy of the same has been placed in the public file. The importer, M/s Impact

Safety Glass Works Pvt. Ltd. had not furnished any non-confidential version of the importer's questionnaire, which had been recorded under para 11 of the preliminary findings. The said importer has made elaborate comments subsequent to the public hearing. The Authority has considered their general submissions where these are supported with the non-confidential version.

- (ii) As regards arguments of importers regarding Non-Disclosure by the Authority about the methodology followed in determining the NIP and injury margin for the domestic industry, the Authority has followed the consistent practice whereunder the methodology for arriving at NIP for the domestic industry is communicated to the domestic industry on a confidential basis. This part of the Disclosure contains the non-injurious price determined for the domestic industry which is based on the confidential information relating to cost of production.
- (iii) As regards non-submission of adequate non-confidential version by the petitioner, the Authority recalls the preliminary findings vide para 21. It has been argued by one of the importers that the method followed in converting quantity from sq. meter to MT has not been disclosed. This information has been furnished by the exporter, M/s PT Mulia and the petitioners to the Designated Authority on a confidential basis. The Authority considers the same as confidential and is of the view that the disclosure of the same is not warranted. The petitioner had given information in Para IV of non-confidential version regarding imports and indexed information regarding market share of imports and domestic industry, capacity utilization, sales volume, sales value, unit price, inventories. The petitioner has claimed confidentiality in respect of information pertaining to profitability, return on investment, figures of price under selling and price under cutting, landed value of imports. The Authority is of the view that the said information being claimed as confidential is of strategic business interest of the petitioner and considers that the information may be treated as confidential as per Rule 7(1).

C. EXAMINATION OF CLAIMS REGARDING NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN.

12. As brought out in the preliminary findings, the Designated Authority sent questionnaires to known exporters of the subject goods in subject countries. Responses were received from the following exporters:

- (i) PT Mulia Glass, Indonesia.
- (ii) PT Abdi Rakyat Bakti, Indonesia.
- (iii) PT Tensindo, Indonesia.

- (iv) M/s Qinhuangdao Huazhou Glass Co. Ltd., China
- (v) M/s Nanning Float Glass Co. Ltd., China

Subsequent to the Preliminary Findings, following arguments have been received from various interested parties / governments of subject countries :

13. Submissions of the Government of the Republic of Indonesia :

Basis for the Normal Value used in the application – In accordance to Article 5.2 of the Anti Dumping Agreement, an application should include evidence of inter alia dumping and should not be based on simple assertion unsubstantiated by relevant evidence. Further, in accordance to Article 5.2 of the Agreement, the Authority shall examine the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application to determine whether there is sufficient evidence to justify the initiation of an investigation. In this regard, the annual accounts of PT Mulia Industrindo is not an appropriate basis to evaluate the cost of production of the subject goods as the holding company of Mulia Glass produces a wide range of diverse products.

14. Submissions of M/s PT Mulia Glass :

- (i) Adjustments on account of packing, ocean freight, insurance, shipping charges, trucking costs, clearance and handling and fumigation charges have been allowed from the export price. However, while calculating ex-factory export price, Authority has decided to resort to weighted average irrespective of thickness and color. We have not exported Float Glass of 2mm and 3mm thickness to India during POI. The majority of exports consist of 12mm ***MT, 4mm Dark Grey ***MT and 5mm Dark Grey ***MT. When calculating the weighted average of the ex-factory export price, Authority should differentiate between clear and tinted / color Float Glass.
- (ii) We do not agree with the Authority's recommendation regarding provisional anti dumping duty on all imports of Float Glass of thickness 2mm to 12mm. The thicknesses which have not been exported to India during POI i.e. 2mm and 3mm should be excluded from imposition of any anti dumping duty.
- (iii) There is no necessity to impose provisional anti dumping duty on our exports to India, pending final determination. Such an imposition should be decided upon only when all our submitted data information has been duly verified and our views taken into account.
- (iv) In the absence of any complete response from the exporter from China in the form and manner prescribed, the authority has determined the

Normal Value in respect of China on the basis of actual cost of production of India's domestic industry after normating it at optimum efficiency level. We have enthusiastically and in good faith participated in the investigation and hence by applying the same standard to PT Mulia Glass, the Authority may arrive at a Normal Value which is even lower than the one mentioned in the case of China.

15. Submissions of M/s Impact Safety Glass Works Pvt. Ltd., Bangalore.

- (i) Asahi has three Float Glass plants in Indonesia which is more than 1/3rd production in Indonesia. When their counterparts are selling material in Indonesia, it is inconceivable that constructed cost of production basis should have been adopted. Even for constructed cost of production, the petitioner has used annual report of Mulia Industries, which is not a producer and is only a holding company having many subsidiary factories and companies. The working of cost of production based on the balance sheet of Mulia Industrindo is just to misguide the Authority to gain advantage in imposition of provisional duties.
- (ii) The adjustment made from export price has not been disclosed. Information with regard to ocean freight and other expenses were disclosed on non-confidential basis in the case before MRTTP and Supreme Court. How the same information can now become confidential. The amount of dumping margin involved has not been disclosed.

16. Views of the domestic industry

The exporters from Indonesia have several cases of anti dumping against them by other authorities. It appears that it is their policy to supply at dumped prices causing immense injury to the interest of the domestic industry.

Examination by the Authority

17. Normal Value for Indonesia

Following exporters from Indonesia had responded to the investigation :

- (i) PT Mulia Glass, Indonesia.
- (ii) PT Abdi Rakyat Bakti, Indonesia.
- (iii) PT Tensindo, Indonesia.

It has been argued by the Government of Indonesia and some importers that the information in the petition was based on estimation and the basis of construction of normal value of PT Mulia on the balance sheet of Mulia Industrindo was incorrect. The Authority is of the view that at the time of initiation of investigation the petition may contain the prima-facie information relating to the

Normal value estimates in support of claim of the alleged dumping. However, the Authority had received the response from M/s PT Mulia and even at the stage of Preliminary Findings, the Normal Value of all the Indonesian exporters was determined on the basis of information furnished by the said exporter. Thus the Authority does not find any merit in the argument of the Indonesian Government and the importers on this account.

18. PT Mulia Glass, Indonesia

The Authority recalls the preliminary findings on the issue of dumping. M/s PT Mulia Glass had submitted detailed information regarding domestic sales, exports to India, cost of production, sale price structure for exports and domestic sales etc. The Authority has also conducted on the spot verification of the exporter's information. The Authority has verified the cost of production of subject goods produced by M/s PT Mulia Glass. Adjustments on account of packing, inland freight, discounts, credit etc. have been verified. As regards inland freight (trucking), the exporter makes domestic sales in various parts of Indonesia which have different freight costs depending upon the location. Based on the quantum of domestic sales made to each region and the weighted average freight cost to each region, a weighted average freight cost of Indo Rupiah *** PMT has been furnished by the exporter which has been considered for adjustment from domestic sales price. The exporter has also given information regarding credit given on the domestic sales. The Authority has also considered the same. Analysis of the domestic sales price of different thickness indicates that most of the domestic sales are in the ordinary course of trade. In the case of 4mm thickness (clear) more than 20% of the sales are not in the ordinary course of trade i.e. less than cost of production plus selling, administration and general costs. The remaining ****% profit making sales have been considered for Normal Value determination. The Authority, therefore, has determined normal value of different thickness types on the basis of domestic sales price of the exporter at ex-factory level. As regards the arguments of the exporter that in the case of China, Normal Value has been determined on the basis of constructed cost of production based on Indian domestic industry, the Authority has determined Normal Value in accordance with Section 9A(1)© of the Customs Tariff Act.

19. PT Abdi Rakyat Bakti, Indonesia.

The Authority recalls the preliminary findings on the issue of dumping. The exporter had furnished only one set of response with all information marked as confidential. No other set of non-confidential information had been furnished as required under the Rule 7(2). The exporter was also advised vide letter dated 6.9.02 to submit non-confidential version, which has not been furnished. The Authority finds that the exporter had not given satisfactory reason for not furnishing non-confidential version. The exporter had also not furnished information regarding cost of production and the Profit & Loss Account and

Balance Sheet. The Authority notes that the exporter has not given any comments or information subsequent to the preliminary findings. The Authority thus holds that the exporter has not fully cooperated in the investigation. The Authority is, therefore, constrained to disregard the information furnished by the exporter in terms of Rule 7(3). The Authority has, therefore, been constrained to rely upon the best available information under Rule-6 (8) for Normal Value determination. The Authority has determined the Normal Value in respect of this exporter on the basis of information available in the case of M/s PT Mulia Glass, Indonesia.

20. PT Tensindo, Indonesia.

The Authority recalls the preliminary findings on the issue of dumping. The information furnished by M/s PT Tensindo, Indonesia was found to be grossly deficient. The exporter has not furnished the required information as pointed out in the preliminary findings. The Authority is, therefore, constrained to rely upon the best available information for Normal Value determination. The Authority has therefore, determined the Normal Value in respect of this exporter on the basis of information available in the case of M/s PT Mulia Glass, Indonesia.

21. Export price in respect of Indonesia:

The Authority recalls the preliminary findings as regards export price determination. Export price in respect of M/s PT Mulia Glass had been determined on the basis of information furnished by the exporter. They have furnished details of exports of Float Glass 'Clear' and 'Dark Grey' in various thickness. The Authority has considered the export prices shown in the questionnaire response. The exporter has shown adjustments on account of packing, ocean freight, insurance, shipping charges, trucking costs, clearance and handling and fumigation charges. The Authority has verified the information relating to adjustments. The ocean freight adjustment has been considered on actual basis as per statement furnished by the exporter during verification. The ex-factory export price has been determined after making above adjustments.

22. Export price in respect of M/s PT Tensindo has been considered on the basis of the furnished information regarding sales to India. There is no response from the exporter subsequent to the preliminary findings. Adjustments on the basis of information available in the case of M/s PT Mulia have been made from the CIF export price to arrive at the export price at ex-factory level.

23. Export price in respect of PT Abdi Rakyat Bakti, Indonesia has been considered on the basis of the furnished information regarding sales to India. There is no response from the exporter subsequent to the preliminary findings. Adjustments on the basis of information available in the case of M/s PT Mulia have been made from the CIF export price to arrive at the export price at ex-factory level.

24. Normal Value for China P.R.

The Authority recalls the preliminary findings on the issue of dumping. None of the exporters from China P.R. had given complete response to the questionnaire sent to them. M/s Qinhuangdao Huazhou Glass Co. Ltd., China, who had stated to have exported the subject goods during the POI, did not co-operate by furnishing the information as per the questionnaire. The other exporter M/s Nanning Float Glass Co. Ltd., China had informed to have not exported float glass during the period of investigation and so they have not filled the questionnaire response. As regards arguments made by importer to adopt the Normal Value in respect of PT Mulia, Indonesia to determine Normal Value in respect of Chinese producers, the Authority does not find merit in the argument as the same is not in conformity with the Anti Dumping Rules. The Normal Value in the case of Indonesia exporters has been determined based on the domestic sales prices in that country. In the absence of complete response from any Chinese exporter, the Authority has determined Normal Value in the case of China on the basis of facts available as per Rule 6(8) of the Rules supra. The Authority therefore confirms in the absence of any complete response from the exporters from China PR in the form and manner prescribed, to make the findings with regard to exports from China PR on the basis of the facts available to it as per rule 6(8) supra. Accordingly, the Authority has determined the Normal Value in respect of China PR on the basis of constructed cost of production. While doing so, the Authority has considered the evidence regarding cost of production furnished by the domestic industry and has referenced the Normal Value with reference to actual cost of production of domestic industry after normating it at optimum efficiency level.

Normal Value and Export Price in respect of other exporters of Indonesia

25. In respect of other non-cooperative exporters, the Authority has determined Normal Value based on evidence of domestic sales price of co-operative exporter. Lowest export price as per co-operative exporter has been adopted.

Dumping Margin :

26. The Authority followed the consistent practice of adopting the principles governing the determination of Normal Value, Export Price and Margin of Dumping as laid down in Annexure I to the anti-dumping rules. Dumping margins have been determined on the basis of a fair comparison of Export Price with the Normal Value in pursuance of the principle laid down in Para 6 of Annexure-1 to the Rules. The comparison is at the same level of trade, i.e. Ex-factory level. As regards concerns expressed by some of the interested parties about proper comparison of Normal Value and export price of different thickness of clear and tinted Float Glass, the Authority has taken due care to compare Normal Value and export price of Float

Glass of different thickness and color to the extent data is available. As regards arguments made by importers about different dumping margins in respect of exporters from Indonesia while the Normal Value being the same, the authority has considered the export price of the respective exporters while determining the dumping margins. Weighted average dumping margin has been arrived at after determining individual dumping margin for different thickness / color type. Based on the Normal Value and export price as determined above, the Authority has determined the following dumping margins(%) :

S. No.	Country	Name of Exporter	Dumping Margin %
1.	Indonesia	M/s PT Mulia	46.71
2.	Indonesia	M/s PT Tensindo	54.63
3.	Indonesia	M/s PT Abdi Rakyat Bakti	78.91
4.	Indonesia	All other exporters.	78.91
5.	China	All exporters.	43.82

D. INJURY AND THREAT OF INJURY

27. Rule 11 of Anti Dumping Rules reads as follows:
"Determination of Injury:

(1) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall record a further finding that import of such article into India causes or threatens material injury to any established industry or materially retards the establishment of any industry in India;

(2) The designated authority shall determine the injury to domestic industry, threat of injury to domestic industry, material retardation to establishment of domestic industry and a causal link between dumped imports and injury, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in accordance with the principles set out in Annexure II to these rules."

28. The principles for determination of injury set out in Annexure-II of the Anti-Dumping Rules lay down that:

a. A determination of injury shall involve an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.

b. While examining the volume of dumped imports, the said Authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports,

either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of Rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price under-cutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.

29. Submissions of the Government of the Republic of Indonesia :

- (i) The notifications of preliminary findings must contain the matters of facts and law which have led to arguments being accepted and rejected. As both sales volumes and selling prices increased in the POI, cash flow must have been positive and not negative as claimed.
- (ii) Determination of the Injury should be based on positive evidence and involve an objective examination of the volume and effect of the dumped imports on prices of the domestic market. The alleged dumped imports have declined. The examination of the findings of the Authority should be reviewed. Imports did not increase in absolute terms as shown in the findings of the Authority.
- (iii) The Authority should re-examine whether imports increased in relative terms compared to demand or production.
- (iv) All factors relating to injury be evaluated. The Authority must explain why and how the alleged dumped imports has caused injury in view of the increases in production, sales volume and value, increased profitability etc. The only explanation provided to support injury is that the return on investment is not sufficient. Even if this were to be the case, a critical evaluation of other factors would have to be provided before a determination of material injury is concluded.
- (v) The Authority has failed to address any other known factors in the preliminary determination, mainly the following :
 - (a) Increase in capacity of the domestic industry,
 - (b) Trade restrictive practices that may encourage the domestic industry trying to set selling price too high.
 - (c) The price impact of a new entrant on the domestic market.

30. Views of M/s T.L. Verma & Co. Pvt. Ltd.

- (i) Even for the two petitioner companies for whom the Authority has determined injury, the determination of injury violates the provisions of Rule 11.

- (ii) Imports from subject countries are not significant – The market share of imports from subject countries was only 1.67% during POI and was 0.71% in 2000-01. At the same time, the share of the petitioner domestic industry increased from 38.37% during 2000-01 to 48.63% during POI. Thus, when the share of the subject imports increased by 0.96%, the share of the domestic industry increased by 10.26%. As per data given in the application, the market size increased from 106 in 2000-01 to 118 in POI (9 months) or 158, annualized. Thus, the market size has increased by over 52% whereas the share of imports from subject countries increased only by 0.96%. The increase in imports from the subject countries can never be treated as 'significant increase in imports' within the meaning of the first sentence of paragraph (ii) of Annexure II. The Authority is required to evaluate the increase with reference to the market context.
- (iii) Sales Volume - Sales volume of the domestic market has increased by over 17%. There is no injury to the domestic industry on this ground.
- (iv) Production – There is no evaluation of injury on production.
- (v) Capacity Utilization – There has been marginal increase in capacity utilization. Therefore, there is no injury on this ground.
- (vi) Inventory - The production is down, sales volume has increased by 17%, inventory could not have increased. It seems that there is some error in the findings.
- (vii) Wages & Employment - These factors do not show any injury to the domestic industry.
- (viii) Profitability – The Authority is required to examine the profitability of the domestic industry during the POI and compare the same with previous period.
- (ix) Return on Capital Employed – The Authority has not given any reason as to why the percentage is considered too low and what percentage of return of capital employed shall be considered adequate.
- (x) Price under Selling – The Authority appears to have determined one single non-injurious price and landed value for all varieties of Float glass. Such a single comparison is wrong. NIP of respective quality / size should be compared with the respective landed value of imports.

- (xi) Price under Cutting – For price undercutting, landed value is to be examined with reference to average selling price of the domestic industry.
- (xii) Price Suppression / Depression – The findings of Authority as regards price suppression / depression are not correct as the petitioners have stated that the industry is realizing a higher price during the POI. When the prices have increased, the question of price depression does not arise.
- (xiii) Actual and Potential negative effect on Cash Flow – The findings are too generic. The Authority is required to determine actual cash flow during POI and compare the same with the cash flow of previous period.
- (xiv) Growth - The findings on this aspect are too generic. The Authority may evaluate this properly.
- (xv) No injury in respect of China – From the information relating to dumping margin and ex-factory export price, it appears that landed value of imports from China would be higher than the NIP determined by the domestic industry. Therefore, imports from China could not have caused any injury to the domestic industry.
- (xvi) Causal Link - No causal link has been established between alleged dumped imports and alleged injury. While determining causal link, the Authority has not evaluated other factors i.e. factors other than dumped imports which are also causing injury to the domestic industry at the same time.

31. Views of M/s Impact Safety Glass Works Pvt. Ltd., Bangalore.

- (i) Over investment in the country has caused injury, if any, to the Indian producers.
- (ii) Petitioner's Group Companies M/s Glaverbel and Glavermas are part of Asahi Group of Company and the said petitioner is part of the same group. M/s Glavindia is the agent in India. The petitioner and M/s Glavindia import the item tinted reflective glass. This activity should have caused injury to the whole domestic industry as this item can be very well produced by any float glass plant. The petitioners have been able to effect impressive price increases during the investigation period. Signs of recovery and prosperity rather than injury are quite visible in the investigation period. Evidently, the imports have had no price effect on the domestic industry.

- (iii) The quantity of imports in terms of domestic production is negligible. The effect of price would be on quantity. However, reverse is the situation in the present case. The alleged price effect had the effect of lowering of the volumes due to the ways adopted by the petitioner.
- (iv) Profits of the domestic industry are increasing over the years. Their profits were at peak in the investigation period as compared to previous two years.
- (v) It is not clear whether reasons for price under selling can be linked to imports.
- (vi) The prices of goods have been increasing constantly for the last two years. The statement made by the domestic industry that they are under constant pressure to reduce the prices is factually not correct.
- (vii) There is no causal link between alleged price under cutting and selling price of the domestic industry.
- (viii) The domestic industry had earlier filed complaint against the same Indonesian exporters alleging that the Indonesian exporters were adopting restrictive trade practice. Thus petitioners have attributed two reasons against the same cause and effect. Having claimed that restrictive trade practices were being employed by the exporters, how can the Indian producers now claim that there is no injury to them due to alleged restrictive trade practice.
- (ix) There is no evidence of material injury to the domestic industry.
- (x) The Designated Authority should also examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injury the domestic industry.

32. Views of the Domestic Industry

- (i) The claim of the domestic industry as regards injury were dealt in the preliminary findings and are not being repeated. In response to the arguments made by other interested parties, the domestic industry has made following submissions :
- (ii) It has been argued by the importers that the market share of imports from subject countries was only 1.67% during the POI which was 0.71% in 2000-01. It has also been argued that the share of the domestic industry has increased much more as compared to the share of the subject imports. It is submitted that the increase in imports has to be seen in comparison to the share held in the preceding period.

Such a comparison would indicate that the share of imports has more than doubled in the POI as compared to the immediately preceding period. The rate of growth of imports is also much higher as compared to the rate of growth of market. The increase in imports may also be re-evaluated after taking into account the imports from Nhava Shava Port.

- (iii) With regard to the increase in sales volume, the importers have failed to appreciate the fact that increase in sales volume need to be analyzed in view of the fact that the total capacity as well as production in the country has gone up due to addition of the new manufacturer. The argument of the importer that an increase of 17% does not indicate injury can at best be considered as an arithmetic exercise and not an economic evaluation of this factor. The Designated Authority is requested to consider that the increase in sales may be evaluated taking into consideration the new capacities.
- (iv) As regards the actual production by the domestic industry, the Authority may appreciate the fact that the increase in production is almost entirely on account of a new manufacturer viz. M/s Saint Gobain.
- (v) With regard to profitability and return on capital employed, the domestic industry has not been able to realize a reasonable rate of return on the huge investments made by it despite the fact that they have the world class technology and have also taken extensive steps to cut costs over a period of time. The dumped imports from subject countries are not allowing the domestic industry to realize any returns which can be considered as reasonable.
- (vi) As regards Authority's findings on price under cutting, the Authority has actually recorded in its findings that the comparison of the average net sales realization of the domestic industry with the landed value of imports has been made to arrive at the extent of price under cutting. The reference to NIP in the table below in the sub-para relating to Price under cutting is an inadvertent typographical error.
- (vii) As regards assumptions made by importer regarding working of Normal Value for China and the non-injurious price, such argument is totally presumptuous in nature, and has no factual or legal force. The Authority is urged to proceed on the basis of information available with it.

Examination by the Authority

33. The Authority has examined the various claims and counter arguments on injury as under:

i) Imports from subject countries:

The total imports from subject countries were 10272 MT in 1999-2000, 2036.11 in 2000-01 and 4406 MT during POI (9 months) or 5874 MT (annualized). Imports from subject countries grew by 188% during POI (annualized) over the previous year. There was overall decline in imports from subject countries during POI in comparison to year 1999-2000. However the share of imports from subject countries in the total imports grew to 96.45% during POI in comparison to the previous year share of 20.87% and in the year 1999-2000 of 67.75%. The Authority finds that there has been significant increase in the dumped imports from subject countries in absolute terms.

ii) Market share:

Market share of imports from subject countries in the total demand for the subject goods has increased from 0.71% in 2000-01 to 1.67% during POI. Market share of the petitioner domestic industry in the total demand of subject goods has not declined during POI. It has increased from 38.37% during 2000-01 to 48.63% during the POI. However, the market share of imports from other countries in total demand has declined during the POI to 0.06% from 2.71% in year 2000-01. The overall demand of the subject goods has increased significantly during the POI in comparison to the previous two years. The increase in market share of the dumped imports from subject countries with reference to the total demand shows that there has been significant increase in imports from subject countries both in absolute terms as well as in relation to the demand in the country.

iii) Production of Domestic Industry

The Authority notes that the capacity, production and capacity utilization of the domestic industry has been as under :

Year	Capacity*	Production*	Capacity Utilization
1999-2000	100	100	76.48%
2000-01	151	156	79.09%
April-Dec. 2001	167	171	78.43%
POI Annualized	223	228	78.43%

*Indexed figures.

The Authority finds that there has been increase in the production capacity of the domestic industry and actual production. However, with reference to the increased capacity in the POI, the capacity utilization has marginally declined by 0.66% during the POI in comparison to the previous year.

iv) Sales Volume:

Sales volumes of domestic industry increased from ** in 2000-01 to *** in POI. This showed an increase of about 17% over the year 2000-01. However, this increase in sales volume is also on account of increase in the capacity of the domestic industry and therefore, this increase in sales cannot by itself be attributed to an improvement in performance.

v) Inventory:

The inventory of domestic industry has increased by 14% at the end of December, 2001 in comparison to the previous year closing on March, 2001. As regards arguments of importer that the inventory could not have increased when the sales volume has increased by 17% and that capacity utilization has come down by 0.66%, the Authority finds that the capacity of the domestic industry had increased from 100 to 167 (indexed) during POI. There was also increase in production from 100 to 171 (indexed). Therefore, the assumptions of the importer are not correct. The increase in inventory is on account of lower sales in comparison to the higher production volume as a result of increased capacity.

vi) Employment:

There has been no impact on the employment level in the domestic industry.

vii) Wages:

There is no effect on the wages of the industry in view of the prevalent labour laws.

viii) Profitability

The Authority notes that the domestic industry has made some marginal profit during the POI.

ix) Price under selling:

The authority has compared the Non-injurious price of the domestic industry with the landed value of imports and has found that there is significant price under selling as a result of dumped imports.

	China	Indonesia
NIP	***	***
Landed value	***	***
Under selling %	***(+ve)	***(+ve)

x) Price under cutting:

In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree. The Authority has compared the average net sales realization of the

domestic industry with the landed value of imports and have found that there has been very significant price under cutting. The imports were having significantly suppressing/ depressing effect on the prices in the domestic market, as the domestic industry has not been able to raise its selling price in view of the dumped imports.

	China	Indonesia
Average Net Sales Realization	***	***
Landed value	***	***
Under cutting %	***(+ve)	***(+ve)

While determining the non-injurious price for the like articles for the domestic industry, the Authority has used the actual cost of production of the subject goods to determine optimum cost of production for the domestic industry which would take into account the normated best consumption norms and the actual price of the raw materials which are consumed for the production of the subject goods during the period of investigation. For calculation of injury margin, the ex-factory non-injurious price determined for the period of investigation has been compared with the landed value of the imported goods.

CONCLUSIONS ON INJURY

34. From the foregoing, the following conclusions are made by the Authority regarding various injury parameters affecting the domestic industry:

- i) There has been an increase in imports of subject goods from subject countries in absolute terms as well as in relation to the demand of subject goods in the country.
- ii) The market share of the dumped imports from the subject countries has increased.
- iii) The selling price of the domestic industry increased during the POI as compared to year 2000-01. However, the same has been below the non-injurious price (NIP) on account of dumped imports.
- iv) The industry has suffered injury due to price undercutting by the dumped imports.
- v) The domestic industry has suffered injury due to price suppression. They have not been able to raise their selling price so as to realize a fair return on the investments as the landed value of the dumped imports has considerably depressed the selling price of the domestic industry.

- vi) Sales Volume of the domestic industry increased during the POI which is on account of increase in the production capacity of the domestic industry. This increase in sales cannot by itself be attributed to an improvement in the performance.
- vii) There has been an increase in the inventory at the end of December, 2001 in comparison to previous year closing on March, 2001.
- viii) There has been no impact on the employment level of the domestic industry.
- ix) There is no effect on the wages of the industry.
- x) The Authority concludes that the most significant cause of injury to the domestic industry has been the price under cutting and price under selling. As a result of lower landed value of imports of subject goods from subject countries, the domestic industry has not been able to realize a fair and reasonable price for its products. This has led to very marginal return on investment. The investments in the Float glass Industry are quite heavy and the low return achieved on the investment by the industry reflects the injury suffered by the industry.
- xi) The above economic parameters cumulatively and collectively establish that domestic industry has suffered material injury on account of dumping.

E. CAUSAL LINK

35. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry the Authority has examined the effect of the dumped imports in accordance with principle (v) of Annexure-II of the Anti-Dumping Rules.

The Authority finds that the most significant cause of the injury to the domestic industry has been the price under cutting and price under selling as a result of the dumped imports from subject countries. As a result of lower landed value of imports of subject goods from subject countries, the domestic industry has not been able to realize a fair and reasonable price for its products. This has led to very marginal return on investment. The investments in the Float glass Industry are quite heavy and the low return achieved on the investment by the industry reflects the injury suffered by the industry. The demand of the subject goods has not decreased but has instead increased and therefore, contraction of demand cannot be attributed as a cause of injury. The Authority also notes that the domestic industry is globally competitive and changes in technology or competition amongst the domestic producers are not the cause of injury. No technological development in the industry or any other such factor which could have resulted in injury to the domestic industry has been noticed.

On the basis of the 'facts available', it is observed that the imports of the subject goods from "other countries " are below the de-minimis level during the period of investigation. The Authority therefore, concludes that the injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports of subject goods from subject countries.

Earlier complaints made by AIFGMA before the Designated Authority, Customs and MRTP Commission.

36. M/s Impact Safety Glass Works Pvt. Ltd., Bangalore and other importers have again raised the issue of AIFGMA having earlier approached the Designated Authority, the Customs Authority and MRTP Commission regarding the imports from Indonesia. The Authority recalls the preliminary findings under para 22 – 24 on this issue and confirms its views.

F. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

37. The purpose of anti dumping duties in general is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market which is in the general interest of the country.

38. The Authority recognizes that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the subject goods or the products manufactured using subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of anti dumping measures would not restrict imports from subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

G. CONCLUSIONS

39. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

- (i) Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes have been

exported to India from subject countries below their normal value;

- (ii) The domestic industry has suffered material injury;
- (iii) The material injury has been caused cumulatively by the dumped imports from subject countries;

40. It is considered necessary to impose definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti dumping duty on the imports of Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes

41. It is decided to recommend the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. The landed price of imports was also compared with the non-injurious price of the domestic industry, determined for the period of investigation. Accordingly, it is proposed that definitive anti-dumping duties be imposed on 'Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes' originating in or exported from the subject countries being cleared under Heading 70.05 of the Schedule I of Customs Tariff Act. The anti-dumping duty shall be the amount mentioned in Col. 9 of the Table below in US \$ per MT.

S.No	Sub-Head ing	Descriptio n of Goods	Specification	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measur ement	Curr ency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	70.05	Float Glass	Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes	Any country other than China	Indonesia	Any producer	PT Mulia Glass	71.16	MT	US\$
2.	70.05	Float Glass	Same as above.	Any country other than	Indonesia	Any producer	PT Tensindo	77.76	MT	US\$

3.	70.05	Float Glass	Same as above.	China Any country other than China	Indonesia	Any producer	PT Abdi Rakyat	81.21	MT	US\$
4.	70.05	Float Glass	Same as above.	Any country other than China	Indonesia	Any producer	All exporters except PT Mulia, PT Tensindo and PT Abdi Rakyat	81.21	MT	US\$
5.	70.05	Float Glass	Same as above.	China	Indonesia	Any producer	Any exporter	81.21	MT	US\$
6.	70.05	Float Glass	Same as above.	Any country	China	Any producer	Any exporter	72.27	MT	US\$

42. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975..

43. Subject to the above, the Authority confirms the preliminary findings dated 20th November, 2002.

44. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act, *supra*.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority